04 - जंतर-मंतर की तीन तस्वीरें और राजनीतिक संदेश

05 - अजित दादा पवार : लोकतांत्रिक नेतृत्व की अविस्मरणीय विरासत

A Daily News Magazine

भोपाल

बुधवार, 22 जुलाई, 2026

06 - एग्रो-होम्योपैथी कृषि क्षेत्र की नई क्रान्ति

07 - ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर 99 हजार की साइबर ठगी

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 320, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

पीके बनाम बीजेपी : बांकीपुर का मुकाबला सिर्फ 'उपचुनाव' क्यों नहीं है?

उमेश कुमार राय

बांकीपुर उपचुनाव पर देशभर की नजर है क्योंकि यहां बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर ने एंट्री कर चुनाव को रोचक बना दिया है। कायस्थ वोटरों का दबदबा, जातिगत समीकरण और स्थानीय समस्याएं, सभी इस मुकाबले को खास बनाते हैं। क्या प्रशांत किशोर (पीके) बीजेपी के किले में सेंध लगा पाएंगे?

बिहार की राजधानी पटना की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव ने सबका ध्यान खींचा है। इसकी वजह है पूर्व चुनावी रणनीतिकार और 'जन सुराज पार्टी' के मुखिया प्रशांत किशोर की एंट्री। बांकीपुर सीट साल 1995 से ही बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस सीट से लगातार पांच बार जीत दर्ज की है और वे नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री भी रहे। लेकिन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इसी वजह से 30 जुलाई को बांकीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। इसी सीट को चुनकर प्रशांत किशोर ने बीजेपी के सबसे सुरक्षित गढ़ में अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दांव खेला है।

बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पटना जिले का एक पक्का शहरी इलाका है। करीब 3.79 लाख वोटरों वाले इस इलाके में कायस्थ वोटर ही हार-जीत तय करते हैं। परिसीमन के बाद यहां के जातिगत समीकरण थोड़े बदल गए हों, लेकिन यहां कायस्थ वोटर आज भी करीब 14 फीसदी हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूतों के साथ-साथ पिछड़ी जातियों और दलित वोटरों की भी अच्छी-खासी आबादी है। यही वजह है कि बीजेपी के पहले उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा 'बंटी' और उनका नामांकन रद्द होने के बाद दूसरे उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा भी कायस्थ ही हैं। बिहार में सवर्णों की कुल आबादी का कायस्थ केवल 0.6 फीसदी हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि सिर्फ कायस्थ वोटों के दम पर चुनाव जीत जाने का दावा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। पटना यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के गेस्ट फैकल्टी और पटना की झुग्गी-बस्तियों पर लंबा काम कर चुके प्रभाकर कुमार ने कहा कि बांकीपुर में वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहता है... ऐसे में झुग्गी-बस्तियों के वोटर यहां बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में करीब एक दर्जन झुग्गियां हैं। इन झुग्गियों से बीजेपी को अच्छे-खासे वोट मिलते हैं, क्योंकि वहां दक्षिणपंथी संगठन बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में महज 41.33 फीसदी वोट पड़े थे, इनमें से नितिन नवीन को 63.34 प्रतिशत वोट मिले थे।

पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों से पहले प्रशांत किशोर ने बड़े-बड़े दावे किए थे। लेकिन, जब एन मौके पर उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा। उनकी 'जन सुराज पार्टी' के 90 फीसदी से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। ऐसे में प्रशांत किशोर ने एक सीट के उपचुनाव के लिए खुद मैदान में उतरने का फैसला क्यों किया? पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि जैसे ही यह सीट खाली हुई, किशोर ने कॉलेज के छात्रों को बांकीपुर में जमीनी सर्वे के काम पर लगाया। सर्वे से साफ हुआ कि बांकीपुर में पलड़ा आज भी बीजेपी का ही भारी है। लेकिन प्रशांत किशोर अपनी अपनी पार्टी की प्रासंगिकता साबित करने के लिए इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि यह सीट सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास रही है, इसलिए यहां कड़ी टक्कर देने भर से भी उनके राजनीतिक कद को एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। जन सुराज से जुड़े अनूप मैथिल कहते हैं, 'हमारा मकसद बिहार को एक नया राजनीतिक विकल्प देना है। हम लोगों तक अपना यह संदेश तभी पहुंचा सकते हैं, जब हम चुनाव लड़ें और जीतें। इसी बीच, चुनावी मैदान में बीजेपी उम्मीदवार का नाम वापस होना पार्टी के लिए भारी फजीहत की वजह बन गया है, जिसने जन सुराज के हाथों में बैठे-बिठाए एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है।

चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की एंट्री के साथ ही एक सीधा और बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर वो किसके वोट बैंक में सेंध लगाएंगे?

जन सुराज से जुड़े एक अंदरूनी सूत्र का कहना है, हमारा टारगेट हर कोई है, चाहे वो आरजेडी का वोटर हो या बीजेपी का। जन सुराज को हर जाति और धर्म के लोगों का साथ मिल रहा है, और युवाओं के बीच तो हमारी अलग ही लोकप्रियता है। लेकिन अगर आप प्रशांत किशोर के चुनावी भाषणों और उनके कैंपेन को करीब से देखें, तो साफ समझ आ जाएगा कि उनके निशाने पर असल में कौन से वोटर हैं।

किशोर अपने भाषणों में सीधे सम्राट चौधरी पर हमला बोल रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर बीजेपी यह उपचुनाव हार जाती है, तो दिल्ली तक यह सीधा संदेश जाएगा कि बिहार की जनता को सम्राट चौधरी बतौर मुख्यमंत्री बिल्कुल मंजूर नहीं हैं।

अभी कुछ दिन पहले ही, जनता दल (यूनाइटेड) यानी जेडीयू के नेता नीरज कुमार का एक पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें वे सम्राट चौधरी की एजुकेशनल डिग्री की प्रामाणिकता पर ही सवाल उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने सीधे सम्राट चौधरी को घेरते हुए उन्हें सात मर्डर केस का 'आरोपी' तक कह डाला है। राजनीतिक पंडितों की मानें तो सम्राट चौधरी पर ये हमले 'सोचे-समझे और रणनीति का हिस्सा' हैं। इसके जरिए पीके सवर्ण वोटरों खासकर ब्राह्मण और भूमिहार वोटरों को अपने पाले में लाने की जुगत में हैं। ये वो वोटर हैं जो सम्राट चौधरी के बढ़ते कद और पिछले महीने भोजपुर के रहने वाले ब्राह्मण युवक भरत तिवारी के कथित पुलिस एनकाउंटर को लेकर बीजेपी-सरकार से काफी नाराज चल रहे हैं। बता दें कि सम्राट चौधरी कोइरी (कुशवाहा) जाति से आते हैं, जो ओबीसी का हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सुमन के अनुसार ने ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उन्हें इससे कोई खास फायदा होने वाला है। इस बार भी आरजेडी ने बनिया समुदाय की रेखा गुप्ता पर ही दांव लगाया है, और उनका चुनाव प्रचार फिलहाल काफी शांत और लो-प्रोफाइल चल रहा है। रणनीति के लिहाज से देखें तो यह शांत और लो-प्रोफाइल चुनाव प्रचार आरजेडी के काम आ सकता है। अगर प्रशांत किशोर सवर्ण वोटों के एक हिस्से को अपने पाले में खींचने में कामयाब हो जाते हैं, तो इससे सीधा फायदा आरजेडी को ही पहुंचेगा।

बांकीपुर की हकीकत ये है कि यह इलाका जलजमाव, पीने के पानी की किल्लत, जर्जर स्कूल-कॉलोनियों और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की भारी कमी जैसी कई बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। लेकिन कोई इस पर ध्यान देने को राजी नहीं है। ऐसे में मतदाता नए विकल्प को आजमा सकते हैं।

(दि क्विंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

भारी हंगामे के बीच पास हुआ यूसीसी बिल

सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग खारिज, हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल पास हो गया। विपक्ष के तीखे विरोध और वॉकआउट के प्रयासों के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही जारी रखते हुए विधेयक को पास घोषित कर दिया।

मध्य प्रदेश की विधान सभा में यूसीसी बिल पास हो गया है। ऐसा करना वाला मध्य प्रदेश देश का चौथा राज्य। इसका मतलब ये है कि अब मध्यप्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के बीच यह बिल पारित हुआ है। इसे सत्ता पक्ष की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। कांग्रेस इस इसको प्रवर समीति के पास भेजना चाहती और कई संसोधन भी चाहती थी लेकिन सरकार ने इसको पास कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने इस बिल को एक तरफा पास कर दिया था।

सत्र की शुरुआत में ही सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को चर्चा के लिए पटल पर रखा। बिल पेश होते ही विपक्ष हमलावर हो गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बिल का कड़ा विरोध करते हुए इसे विस्तृत समीक्षा के लिए प्रवर समिति (सेलेक्ट कमेटी) के पास भेजने की मांग की। हालांकि, सरकार ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक शुरू हो गई।

● सीएम मोहन और उनके विधायकों ने लगाए 'जय श्री राम' के नारे

यूसीसी बिल पास, अब राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार- विधानसभा से यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित होने के बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद इसका राजपत्र (गजट) में नोटिफिकेशन जारी होगा।

7,765.77 करोड़ के अनुपूरक बजट पर आज होगी चर्चा

मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश कर दिया। कुल 7,765.76 करोड़ रुपए के इस बजट में सबसे अधिक 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिए किया गया है। यह राशि विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं और भूमि अधिग्रहण के भुगतान पर खर्च होगी।

जीतू पटवारी बोले- यूसीसी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी का मुद्दा उठा रही है।

विधानसभा में मुर्दों की तरह लेटे कांग्रेस विधायक, उमंग सिंघार बोले- वास्तविक मुद्दों पर निष्क्रिय है सरकार

मध्य प्रदेश विधानसभा में दूसरे दिन भी कांग्रेस विधायकों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करते हुए बीजेपी सरकार को मुर्दों की सरकार करार दिया है। साथ ही आरोप लगाया है कि सरकार जनता के वास्तविक मुद्दों पर पूरी तरह से निष्क्रिय है। उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश की जनता की समस्याओं के प्रति मुर्दों की तरह सोई हुई है। किसानों को खाद की कमी का सामना करना पड़ रहा है, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और प्रदेश में घोटालों की परतें खुल रही हैं, लेकिन सरकार इन गंभीर मुद्दों पर मौन है।सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी कांग्रेस ने यूसीसी के विरोध में सांकेतिक नाटक का मंचन किया।

मप्र के लिए 21 जुलाई का दिन ऐतिहासिक, शरिया नहीं समान कानून होना चाहिए : सीएम

सीएम मोहन यादव ने जो कहा था, वो कर दिखाया है। 21 जुलाई मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद सभी धर्मों के लोगों का जीवन एक कानून के मुताबिक चलेगा। न प्रदेश में कोई तीन तलाक ले सकेगा, न हलाला कर सकेगा, न लिव-इन रिलेशनशिप का दुरुपयोग कर सकेगा और न ही किसी की संपत्ति पर अधिकार जमा सकेगा। यूसीसी के पास होने के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि एक से ज्यादा विवाह अब अपराध होगा। एक से ज्यादा विवाह पर बहनों को कष्ट होता है, उससे उनको मुक्ति मिलेगी। हमारी सरकार प्रदेश की आधी आबादी को बहनों को उनका हक दिलाएगी।

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

क्यों उपेक्षित हैं हमारी प्रार्थनायें,
देवता इस प्रश्न का उत्तर बतायें।
आपको उनसे निराशा ही मिलेगी,
मत तलाशें इस क़दर संभावनायें ।
लग गयी हैं स्वार्थ के झोकों से हिलने,
सिर्फ खूंटी पर टंगी हैं आस्थायें ।
कुछ हमारे मौन का भी अर्थ समझें,
हो नहीं पाती मुखर सब भावनायें ।
अब हमारे देश में है लोकशाही,
आइये इस चुटकुले पर मुस्कुरायें।
जब किया है प्यार का बेशर्त सौदा,
फिर नफ़ा-नुकसान क्या जोड़े-घटायें।

- डॉ. दिनेश त्रिपाठी

पीएम आवास के बाहर कांग्रेस का हाई-वोल्टेज ड्रामा

राहुल, प्रियंका, अखिलेश को पुलिस ने हिरासत में लिया

● पुलिस स्टेशन के बाहर विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं का था जमावड़ा

नईदिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सोमवार को मचे भारी बवाल के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर खाली करवा लिया था लेकिन देर रात एक बार फिर से प्रदर्शनकारी वहां पर जुटने लगे। रात को प्रदर्शनकारियों के बीच अभिजीत दीपके ने कहा है कि अब सरकार से कोई बात नहीं होगी जिसे भी बात करनी होगी वो जंतर-मंतर पर आएगा। दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर विपक्षी नेता और कार्यकर्ता जमा हुए हैं। यहीं पर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ नेताओं को हिरासत में लेने के बाद थोड़ी देर पहले लाया गया था। लोक कल्याण मार्ग पर विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे राहुला गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

कहां ले जा रहे हो पुलिस भाई? : अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत के दौरान गाड़ी में बैठे हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कहां ले जा रहे हो पुलिस भाई?

कई राज्यों में भारी बारिश

● जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से बुरे हाल, दो दिन में 23 की मौत
● गुवाहाटी में लैंडस्लाइड, असम में 1.7 लाख लोग प्रभावित

नई दिल्ली (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। पिछले दो दिनों में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। पुंछ और राजौरी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सात लोग अब भी लापता हैं। लगातार बारिश के कारण राहत और बचाव अभियान प्रभावित हुआ। सोमवार को भारी बारिश के बाद असम के गुवाहाटी में लैंडस्लाइड हुई। इसके बाद नेशनल हाईवे-715 का एक हिस्सा पानी में डूब गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य के 12 जिलों में 1.70 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। एमपी के लगभग 90 फीसदी हिस्से में अगले 4 दिन यानी 23 जुलाई तक हल्की बारिश का दौर बना रहेगा।

हिमाचल में बादल फटने से तबाही, बह गए 6 घर

हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा के शाहपुर क्षेत्र में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। शाहपुर की बोह घाटी के स्पैडा और गढ़गून गांव में बादल फटने से आई बाढ़ में छह मकान बह गए हैं। प्रशासन की टीम ने सूचना मिलते ही प्रभावित क्षेत्र का रुख कर लिया। बताया जा रहा है लोगों ने भागकर जान बचाई। पहाड़ी पर धमाका होने के बाद अचानक बाढ़ और मलबा आ गया, जो छह मकानों को अपने साथ बहाकर ले गया। एसडीआरएफ के पहुंचने के बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू होगा। कई घरों का नामोनिशान नहीं बचा है। बाढ़ के बाद आसपास के लोग सहमे हुए हैं। पहाड़ी से सटे क्षेत्र में जिनके घर हैं, वह मकान छोड़कर बाहर आ गए हैं। लोग घरों में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। प्रशासन ने एसडीआरएफ को बुलाया है। प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट में किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ है।

सिक्किम की निर्माणाधीन टनल पर हुआ लैंडस्लाइड

10 मजदूरों की हो गई मौत, 17 अब भी हैं फंसे

मलबे से सुरंग बंद, रेस्क्यू करने गए वर्कर बेहोश

गंगटोक (एजेंसी)। सिक्किम में सोमवार को एक टनल पर लैंडस्लाइड होने से उसका एंट्री गेट बंद हो गया, जिससे अंदर मौजूद 27 मजदूर फंस गए। इनमें से 10 की मौत हो गई। मृतकों में 3 की पहचान अभी नहीं हो पाई है, जबकि 17 मजदूर अब भी फंसे हैं। नामची जिले के मामरिंग स्थित समरदुंग सुरंग में निर्माण कार्य चल रहा था। एसपी सोनम डोल्मा ने बताया कि फंसे हुए मजदूरों की संख्या 27 से कम या ज्यादा भी हो सकती है।

● बंगाल से स्पेशल रेस्क्यू टीम लाई गई- जिला अधिकारी तमलिंग ने बताया कि दोपहर करीब 3.40 बजे प्रशासन को हादसे की खबर मिली। इसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं। सुरंग में पटेल इंजीनियरिंग के 21 और एनएचपीसी के 6 समेत कुल 27 मजदूर फंसे होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल से भी गैस-रोधी उपकरणों के साथ एक स्पेशल रेस्क्यू टीम लाई गई है। एंबुलेंस को तैयार रखा गया है। बचाव दल गैस मास्क पहनकर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 22 जुलाई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

भोपाल में 11 वर्षीय बच्चे को मिली नई जिंदगी

छत से गिरने पर दिमाग में जम गया था खून, डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर बचाई जान

भोपाल (नप्र)। भोपाल में छत पर खेलते समय गिरने से गंभीर रूप से घायल हुए 11 वर्षीय रोहित की जटिल ब्रेन सर्जरी कर डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली। हादसे में रोहित के सिर में गंभीर चोट लगी थी और उसके मस्तिष्क में खून जमा हो गया था। करोंद स्थित अटल मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जरी विशेषज्ञों ने तत्काल ऑपरेशन कर स्थिति को नियंत्रित किया। अब बच्चे की हालत स्थिर है और वह सामान्य रूप से बातचीत कर रहा है। जानकारी के अनुसार, रोहित घर की छत पर खेल रहा था, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया। हादसे के बाद वह बेहोश हो गया और उसकी नाक से खून निकलने लगा। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने

प्राथमिक जांच के बाद सीटी स्कैन कराया। जांच में सामने आया कि रोहित के मस्तिष्क में एक्यूट राइट टेम्पोरो-पैरिएटल एपिड्यूरल हेमेटोमा, 7 मिमी लेफ्टवर्ड मिडलाइन शिफ्ट और मल्टीपल हेमरेजिक कंट्यूजन जैसी गंभीर चोटें हैं।

पीएम आवास के पास धरने पर बैठे राहुल और प्रियंका

- राहुल ने विपक्षी नेताओं को बांटे प्लास्टिक बैंड्स, हाथ बांधकर प्रदर्शन
- केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से मिले, धरना खत्म करने को कहा, राहुल, अखिलेश हिरासत में

नई दिल्ली (एजेंसी)। पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस के कई नेता दिल्ली में पीएम आवास के पास धरने पर बैठ गए हैं। इनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं। कांग्रेसी पीएम और गृहमंत्री इस्तीफा दो के नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शन के बीच यहां पुलिस ने पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। कांग्रेस का यह प्रदर्शन बेहद सीक्रेट रहा। राहुल समेत सभी नेता कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर से पीएम आवास तक पैदल मार्च करके पहुंचे। जब ये लोग 100 मीटर दूर थे तब मीडिया को जानकारी दी गई। वहीं धरनास्थल से राहुल गांधी और अखिलेश को हिरासत में ले लिया गया था।

हाथ बांधे प्रदर्शन करते हुए नजर खरगे- मल्लिकार्जुन खरगे अपने जन्मदिन के मौके पर हाथ बांधे प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वह अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे क्योंकि यह जश्न मनाने का नहीं, बल्कि जवाबदेही मांगने का दिन है। मल्लिकार्जुन खरगे ने छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के बच्चों को दमन नहीं, न्याय चाहिए। खरगे ने एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि वह अपने जन्मदिन पर

जश्न नहीं मनाएंगे। उन्होंने कहा, 'आज जश्न मनाने का दिन नहीं है। यह जवाबदेही मांगने का दिन है। लोकतंत्र बहाल करो।' राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वह कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों, शुभचिंतकों और उन सभी नागरिकों के आभारी हैं।

हमारे बच्चे दमन के नहीं, न्याय के हकदार- खरगे ने छात्र-केंद्रित परीक्षा प्रणाली लागू करने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष ने राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त, स्वतंत्र और योग्यता आधारित शिक्षा व्यवस्था बनाने तथा शिक्षा पर अधिक खर्च किए जाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि परीक्षा में धांधली होने पर छात्रों को अनिवार्य पुनर्परीक्षा और मुआवजे का वैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। खरगे ने इस बात पर जोर दिया, 'हमारे बच्चे दमन के नहीं, न्याय के हकदार हैं।' खरगे का जन्म 21 जुलाई, 1942 को हुआ था।

संक्षिप्त समाचार

सोनम वांगचुक को मेदांता शिफ्ट करने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी गीतांजलि की याचिका पर दिया फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता शिफ्ट करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मेदांता उनके इलाज के लिए डॉक्टरों का एक पैनल बनाएगा। कोर्ट ने यह आदेश उनकी पत्नी

गीतांजलि अंगमो की याचिका पर दिया है। सोनम 28 जून से भूख हड़ताल पर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद 18 जुलाई को पुलिस उन्हें जंतर-मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई थी। सोनम की पत्नी ने कोर्ट में याचिका लगाकर उन्हें पसंद के अस्पताल में शिफ्ट कराने की मांग की थी। उधर, कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर पर मंगलवार को 32वें दिन प्रदर्शन जारी है। दोपहर 12 बजे तक आंदोलनकारी पहुंच गए थे।

नेपाल में 1 रुपए के सिक्के से हटाया विवादित नक्शा

बालेन शाह ने लिया फैसला, बचा बवाल, देश में घिरे

काठमांडू (एजेंसी)। नेपाल की बालेन शाह सरकार के नेपाल के नए डिजाइन वाले 1 रुपये के सिक्के से विवादित नक्शे को हटाने पर बवाल मच गया है। नेपाल की पूर्ववर्ती केपी ओली सरकार ने चीन के इशारे पर यह विवादित नक्शा जारी किया था जिसमें भारत के लिंपियाधुरा, कालापानी और

लिपुलेख को नेपाली इलाका दिखाया गया था। इस नक्शे को लेकर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। अब बालेन शाह सरकार ने नेपाल के 1 रुपये के सिक्के पर से विवादित नक्शे की जगह पर एक बौद्ध मठ की तस्वीर को छापा है। इसे जहां भारत की बड़ी जीत की तरह से देखा जा रहा है, वहीं इसको लेकर नेपाल में विवाद शुरू हो गया है। नेता भीम रावल ने बालेन सरकार को धोखेबाज बताया।

अन्ना हजारे प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज से नाराज

सरकार से कहा-सभी मुद्दे सहमति से सुलझाए जा सकते हैं

मुंबई (एजेंसी)। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली में सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हो गई। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जंतर-मंतर से संसद तक निकाले गए

मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की। जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। इस घटना के बाद देशभर की कई विपक्षी पार्टियों ने सरकार की आलोचना की।

राज्यपाल-कुलसचिव को हाईकोर्ट का नोटिस

अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई, सेवानिवृत कर्मचारी से जुड़ा मामला; अगली सुनवाई 4 अगस्त को

जबलपुर (नप्र)। मध्यप्रदेश में संभवतः पहली बार किसी अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्यपाल एवं विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (आरडीवी) के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. आर.बी. दुबे की याचिका पर की गई।

हाईकोर्ट ने राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगूभाई पटेल, कुलसचिव डॉ. रविशंकर सोनवाल और उपकुल सचिव पवन साहू को नोटिस जारी कर 4 अगस्त तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

क्या है मामला

डॉ. आर.बी. दुबे की नियुक्ति 10 मई 2000 को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर हुई थी। उन्होंने 29 जुलाई 2006 से प्रभावी होने वाला इस्तीफा विश्वविद्यालय को सौंपा था। हालांकि बाद में उन्होंने 14 जुलाई 2006 को लिखित आवेदन देकर अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 13 जुलाई 2006 को जारी आदेश के आधार पर उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। डॉ. दुबे का तर्क था कि प्रभावी तिथि से पहले ही इस्तीफा वापस ले लिया गया था, इसलिए उसे स्वीकार करना कानूनन गलत था।

हाईकोर्ट ने रद्द किया था इस्तीफा स्वीकार करने का आदेश

मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी को इस्तीफा प्रभावी होने या स्वीकार किए जाने से पहले वापस लेने का अधिकार है। जस्टिस एम.एस. भट्टी की एकलपीठ ने डॉ. दुबे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विश्वविद्यालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसके तहत उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि प्रभावी होने से पहले त्यागपत्र वापस लिया जा सकता है और ऐसे इस्तीफे को स्वीकार करना कानून के विपरीत है।

अब वेतन भुगतान को लेकर अवमानना याचिका

हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद डॉ. दुबे ने बकाया वेतन और अन्य देयकों के भुगतान को लेकर अवमानना याचिका दायर की। उनका आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने निर्देशों का पालन नहीं किया। मंगलवार को जस्टिस विशाल मिश्रा की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए 15 जुलाई 2026 को याचिका पर संज्ञान लिया और सभी अनावेदकों को आरएडी मोड के माध्यम से नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

बाग प्रिंट कला के शिल्पकार मोहम्मद आरिफ़ खत्री मानद डॉक्टरेट से सम्मानित

भोपाल। मध्यप्रदेश की विश्वविख्यात बाग प्रिंट कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाले मास्टर शिल्पकार मोहम्मद आरिफ़ खत्री को भारतीय

पारंपरिक बाग प्रिंट हस्तशिल्प के संरक्षण, संवर्धन, नवाचार एवं वैश्विक स्तर पर इसके प्रभावी प्रचार-प्रसार में उनके असाधारण योगदान के लिए उत्तर प्रदेश के माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर द्वारा डॉक्टर ऑफ लेटर्स (मानद डॉक्टरेट) की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया।

यह सम्मान विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में प्रदान किया गया। समारोह का आयोजन सेठ गंगाप्रसाद माहेश्वरी सभागार, सहारनपुर में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलाधिपति एवं गुजरात की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने ऑनलाइन माध्यम से की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), मोहाली के निदेशक प्रो. अनिल कुमार त्रिपाठी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. वाई. विमला, उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव सुधीर बोबडे ने मोहम्मद आरिफ़ खत्री को मानद उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। मानद डॉक्टरेट किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च अकादमिक सम्मान माना जाता है। यह उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देकर समाज, संस्कृति, कला, शिक्षा अथवा राष्ट्र के लिए स्थायी और प्रेरणादायी कार्य किए हों। मोहम्मद आरिफ़ खत्री को यह सम्मान भारतीय पारंपरिक बाग प्रिंट कला को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने और विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए प्रदान किया गया। मोहम्मद आरिफ़ खत्री को बाग प्रिंट की विरासत अपने दादा शिल्प गुरु इस्माइल सुलेमानजी खत्री तथा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिल्पकार अब्दुल कादर खत्री से प्राप्त हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को दी सरेंडर की सलाह

पूछा-गिरफ्तारी का कारण नहीं बताने का मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया

इंदौर/नई दिल्ली (एजेंसी)। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने की सलाह दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि या तो वह मेघालय सरकार की अपील पर मामले के गुण-दोष को देखते हुए फैसला करेगी या फिर सोनम को समर्पण करने का निर्देश देकर जांच एजेंसियों को आगे पूछताछ का अवसर देगी। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

सोनम के आचरण पर भी उठाए सवाल- सुप्रीम कोर्ट ने वारदात के बाद सोनम के व्यवहार और उसके कानूनी तर्कों पर भी सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि गिरफ्तारी के समय कारण नहीं बताए जाने का मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया गया। इस पर सोनम के वकील ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा और कहा कि वे गुरुवार तक अपना जवाब दाखिल करेंगे। मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोनम की जमानत का विरोध करते हुए अपनी बात रखी।

यूपी की 50 हजार छात्राओं को मुफ्त में मिलेगी स्कूटी

- रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत योगी सरकार का बड़ा तोहफा

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश की छात्राओं को योगी कैबिनेट से बड़ा तोहफा मिला है। मेधावी छात्राओं को परीक्षा में अच्छा करने के लिए फ्री स्कूटी देने वाली स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को आज मंगलवार 21 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दिखा दी गई है। इस योजना के तहत 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में ग्रेजुएशन में हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की टॉप-5 छात्राओं को सरकार की ओर से मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी, प्राइवेट, सेल्फ फंडिंग या अन्य मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है।

छह एमपी के शिवसेना में विलय की मंजूरी का विरोध

- सुप्रीम कोर्ट पहुंची उद्धव सेना, बेंच ने कहा-वादा नहीं कर सकते

नई दिल्ली (एजेंसी)। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 6 सांसदों की एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले को चुनौती देने के लिए पार्टी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि इस मामले पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी जाए। हालांकि, सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना (यूबीटी) की ओर से सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने इस मामले को सीजेआई के सामने रखा।

- **संसद में मेरा कामकाज पूरी तरह से ठप-** सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने जब उद्धव सेना के वकील से तत्काल सुनवाई की आवश्यकता के बारे में पूछा तो उन्होंने अदालत से कहा,एक राजनीतिक दल के तौर पर संसद में मेरा कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। ये सांसद मेरे साथ नहीं हैं। स्पीकर ने इनका दूसरी पार्टी में विलय को मंजूरी दे दी है।

'मेड इन इंडिया' का बजा डंका! 2026 में बढ़ा रक्षा निर्यात

6 देश भारत से खरीद सकते हैं अस्त्र मिसाइल

- सऊदी अरब, इंडोनेशिया और आर्मेनिया से बातचीत है जारी

रियाद/येरेवान/नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में अपनी क्षमता साबित कर चुकी भारत की अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल में आर्मेनिया और सऊदी अरब समेत 6 देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। यह मिसाइल पहले से ही एसयू-30 एमकेआई फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेटेड है और इसके निर्यात को लेकर बातचीत की जा रही है। इस मिसाइल को बेचने की बात उस वक्त हो रही है जब वित्त वर्ष 2026 में भारत का रक्षा निर्यात बढ़कर 38,424 करोड़ रुपया हो गया है। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच अस्त्र बियॉन्ड-विजुअल-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइलों के लिए सैद्धांतिक सहमति बनी थी। इस समझौते ने इस स्वदेशी हथियार प्रणाली में वैश्विक दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है। द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम छह देश इस मिसाइल को खरीदने के लिए भारत से बात कर रहे हैं जिनमें आर्मेनिया और सऊदी अरब शामिल हैं।

- **'अस्त्र' मिसाइल रचेगी नया इतिहास-** भारत और इंडोनेशिया के बीच अस्त्र मिसाइल की संख्या और कीमत को लेकर आगे बात की जाएगी। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि आर्मेनिया अस्त्र मिसाइलें हासिल करने के लिए भारत के साथ बातचीत के एक एडवांस स्टेज में है। इन मिसाइलों को भारतीय वायुसेना के एसयू-30एमकेआई लड़ाकू विमानों से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ

सफल इस्तेमाल किया गया था। आर्मेनिया और सऊदी अरब के साथ बातचीत इस हथियार प्रणाली को उनके विमानों में इंटीग्रेट करने पर केंद्रित है। आर्मेनिया ने एसयू-30 एमआई लड़ाकू विमानों में अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल प्रणाली को एकीकृत करने की बात की।

- **आर्मेनिया बन चुका है भारत का बड़ा रक्षा खरीददार-** आर्मेनिया पहले ही भारतीय हथियार खरीदने वाले शीर्ष देशों में शामिल हो चुका है। वो पहले ही आकाश सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति वेपन-लोकेटिंग रडार, 155एमएम एडवांस्ड टोव्ड आर्टिलरी गन सिस्टम होवित्ज़र और एंटी-ड्रोन सिस्टम खरीद चुका है। रॉयल सऊदी एयर फोर्स अमेरिकी यूरोफाइटर टाइफून जैसे अलग-अलग तरह के विमानों का इस्तेमाल करती है।

डीआरडीओ ने बनाया है अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल

अस्त्र मिसाइल को डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने बनाया है। अस्त्र एमआई-1 की स्पीड मैक 4.5 है और इसकी रेंज 80 से 110 किलोमीटर के बीच है। भारत ने एमआई-2 का भी टेस्ट कर लिया है जिसकी रेंज 200-240 किलोमीटर है। रैमजेट इंजन वाला एमआई-3 वर्शन अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और इसकी प्रस्तावित रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी गारंटी : मंत्री राजपूत

खाद्य मंत्री बोले, सरकार की मंशा है कि कोई भूखा न सोए

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम केवल खाद्यान्न वितरण की योजना नहीं, बल्कि गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का संवैधानिक आधार प्रदान करने वाला सामाजिक न्याय का सशक्त माध्यम है। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गरीब कल्याण के संकल्प और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य का कोई भी पात्र परिवार खाद्यान्न के अधिकार से वंचित न रहे और भूखा न सोए। मंत्री श्री राजपूत भोपाल के कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में राज्य खाद्य आयोग एवं केन्द्रीय नीति आयोग के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 : प्रगति, चुनौतियां और भविष्य की दिशा विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

उचित मूल्य दुकान तक खाद्यान्न पहुँचते ही उपभोक्ता को मैसेज– मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि अब वितरण केंद्र से उचित मूल्य की दुकान तक तथा दुकान से उपभोक्ता तक राशन की प्रत्येक जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का उद्देश्य केवल राशन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र हितग्राही तक उसका अधिकार समय पर, पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ पहुँचाना है। इसी सोच के अनुरूप मध्यप्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक सुधार किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप व्यवस्था अधिक आधुनिक, पारदर्शी और जनकेंद्रित बनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है। पीओएस मशीनों के माध्यम से प्रमाणीकरण, ई-केवाईसी, डिजिटल राशन वितरण, ऑनलाइन निगरानी तथा संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला की रियल टाइम मॉनिटरिंग से खाद्यान्न वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता दोनों बढ़ी हैं। इससे अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगा है और हितग्राहियों का विश्वास भी मजबूत हुआ है। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि विकसित मध्यप्रदेश का सपना तभी साकार होगा, जब प्रत्येक नागरिक को भोजन, पोषण और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार पूरी तरह सुनिश्चित हो। प्रदेश सरकार इसी लक्ष्य के साथ निरंतर कार्य कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र परिवार किसी भी परिस्थिति में अपने अधिकार से वंचित न रहे।

मप्र के नव निर्माण में समाज – सरकार की संयुक्त भागीदारी हो

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, जनसेवा से जुड़े संगठनों और नागरिकों से आह्वान किया कि वे प्रत्येक पात्र हितग्राही तक उसका अधिकार पहुँचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएँ। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से ही भूख-मुक्त, कुपोषण-मुक्त, आत्मनिर्भर और विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण का संकल्प साकार होगा। प्रदेश में बुजुर्ग और विकलांग उपभोक्ता खाद्यान्न लेने के लिये किसी भी व्यक्ति को नामित कर सकते है। नवाचार के रूप में आपका राशन-आपके द्वार योजना लागू की गई है। इसमें राशन की गाड़ी गाँवों में ही जाकर उपभोक्तओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।

अधिकारियों की टीम अन्य राज्यों की योजनाओं का करेगी अध्ययन

मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि अधिकारियों की एक टीम दूसरें राज्यों में भेजी जाएगी। यह टीम उन राज्यों में संचालित बेहतर योजनाओं का अध्ययन कर रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में जो भी महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे, उन पर विचार कर अमल में लाया जाएगा। मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सचिव श्री श्रीमन शुक्ला ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी दी।

इस अवसर पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नीति आयोग के पूर्व सदस्य - प्रो. रमेशचंद्र, म.प्र. राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष - प्रो. वीरेन्द्र कुमार मल्होत्रा, आयुक्त खाद्य श्री भास्कर लक्षकार, डॉ. योगेश सूरी, नीति आयोग एवं देश के विभिन्न राज्यों से खाद्य आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव सहित, खाद्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

सरकारी अधिकारी बनने के बाद पत्नी ने पति को छोड़ा

महिला आयोग में पहुंच रहे केस, पति बोला– पत्नी का लड़की से संबंध, मुझे जान का खतरा

भोपाल (नप्र)। भोपाल में एक महिला असिस्टेंट डायरेक्टर (टीसीपी) बनने के बाद अपने पति पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाकर बच्चे के साथ मायके चली गई। शादी के 20 साल बाद महिला ने महिला आयोग में शिकायत कराई और पति से तलाक की मांग की।

महिला आयोग पहुंचे पति ने बेंच के सामने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है। इस उम्र में वह अकेला कहां जाएगा। पति सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर है।

एक अन्य मामले में पति ने अपनी पत्नी पर दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध के आरोप लगाए। पति ने कहा कि मुझे अपनी पत्नी से जान का खतरा है। जबकि पत्नी ने पति पर उसकी अश्लील फोटो वायरल करने, जबरन अबॉर्शन कराने और दहेज के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया।दरअसल, महिला आयोग में पेंडिंग केसेस की जनसुनवाई चल रही है, जिसमें सोमवार को 30 मामलों की सुनवाई की गई। इसी दौरान यह मामले भी सामने आए।

केस–1 – असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के बाद पति को छोड़ा

शादी के 20 साल बाद महिला ने पति पर मानसिक प्रताड़ना और पैसे के लेन-देन की महिला आयोग में शिकायत की। जिसकी सुनवाई में महिला नहीं पहुंची, पर उसके पति ने बताया कि हमारी शादी में सब ठीक था। आज भी मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं।वह बिना मुझसे कुछ कहे चली गई और मेरे बेटे को भी साथ ले गई। मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। मैं उनके साथ उनके मायके में भी रहने को तैयार हूं। पति ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की नौकरी लगी है, वह बदल गई है।

पति बोला– प्रताड़ित होती तो आईवीएफ से बच्चा कैसे होता?– पति ने कहा कि हमारा बेटा आईवीएफ से हुआ है। अगर इनके साथ मानसिक प्रताड़ना होती तो आईवीएफ से बच्चा होना संभव ही नहीं था। पति बोला, उसके जाने के बाद मेरी मां को भी पैरालिसिस का दूसरा अटैक आ चुका है। यह हमारी दूसरी शादी थी। अब इस उम्र में मैं तलाक लेकर कैसे जीवन गुजारूंगा।

केस–2– पति बोला– मुझे पत्नी से जान का खतरा

पति ने आयोग में दावा किया कि पत्नी के दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध हैं। उसने कहा कि इस संबंध में उसने न्यायालय में दस्तावेज और साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं। हालांकि पत्नी ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया है। आयोग के समक्ष दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे।

महिला आयोग के समझाने पर पति ने कहा, मुझे अपनी पत्नी से जान का खतरा महसूस होता है। मैंने अपनी पत्नी और इनके पार्टनर को फोन पर बात करते हुए सुना है। ये मुझे बीच से हटाने की बात कर रहे थे। अगर कभी इसने मेरे खाने में जहर मिला दिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।

कमरे में कैमरे लगाने का आरोप

महिला ने आरोप लगाया कि उसके बेडरूम में कैमरे लगाए गए और उसकी जानकारी के बिना निजी वीडियो रिकॉर्ड किए गए। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए गए, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। महिला ने कहा कि इस पूरे मामले की शिकायत उसने पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों से भी की है।

महिला बोली– कमरे में बंद रखा, बच्चे का अबॉर्शन कराया

महिला का आरोप है कि कई बार उसे कमरे और बाथरूम में बंद रखा गया। उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। महिला बोली, मेरे पति का उनकी मौसी की लड़की के साथ अवैध संबंध है। मेरा ससुर भी मेरे साथ गलत हरकत करता है।

महिला ने आरोप लगाया कि मेरे पति ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा अबॉर्शन कराया। मुझे 10 से 12 दिन हॉस्पिटलमें भर्ती कराया। तीन महीने तक टायफाइड कराकर बिस्तर पर मरने के लिए छोड़ दिया। पत्नी ने बताया कि मेरा मायका नागपूर है। भोपाल में मेरे ससूराल वाले मुझे घर में अकेले छोड़कर भाग गए। मैं कई सालों से घर में अकेले रह रही हूं। मेरा खर्चा मेरे मायके वाले देते है।

पति ने सभी आरोपों से किया इनकार

पति ने पत्नी के सभी आरोपों को निराधार बताया। उसका कहना है कि उसने स्वयं पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन उसकी शिकायत पर भी उचित कार्रवाई नहीं हुई। उसने आयोग के सामने दावा किया कि उसके पास अपने पक्ष के समर्थन में दस्तावेज और साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

शादी के पहले दिन से दहेज की मांग का आरोप

वहीं, महिला ने आयोग को बताया कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष सोना, नकदी और अन्य सामान की मांग करते थे। जब उसके परिवार ने लगातार आर्थिक मदद देने से इनकार किया तो उसके साथ दुर्व्यवहार शुरू हो गया। महिला का आरोप है कि उसे बार-बार ताने दिए गए और प्रताड़ित किया गया।

अब लोकायुक्त के सामने पेश होंगी एसीएस दीपाली रस्तोगी

पोषण आहार घोटाले की जांच में लोकायुक्त ने भेजे स्मरण पत्रों को विभाग ने नहीं दी तवज्जो

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े अरबों रुपए के टेक होम राशन और पोषण आहार घोटाले की जांच तेज हो गई है। लोकायुक्त संगठन ने इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों पर शिकंजा कसते हुए पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, तत्कालीन एसआरएलएम (स्त्र्र्र्रू) सीईओ ललित मोहन बेलवाल समेत कई अफसरों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है।

विधानसभा में सरकार द्वारा दिए गए जवाब और लोकायुक्त के रिकॉर्ड में दर्ज तथ्यों के बीच विरोधाभास सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है।

दीपाली रस्तोगी को लोकायुक्त के सामने होना होगा पेश– लोकायुक्त संगठन द्वारा कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव (ष्टस्) दीपाली रस्तोगी अब तक च्कार्यालयीन व्यस्तताज्ज का हवाला देकर पेश नहीं हुईं। विधानसभा में सरकार ने भी स्वीकार किया कि व्यस्तता के कारण वे लोकायुक्त कार्यालय नहीं जा सकीं। अब लोकायुक्त ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

हमारी सरकारें विकसित भारत और विकसित मध्यप्रदेश के संकल्प को कर रही है साकार : डॉ. महेन्द्र सिंह

दतिया/भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने मंगलवार को दतिया स्थित भाजपा चुनाव कार्यालय से विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर संबोधित किया। भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रचार रथों के माध्यम से सभी मंडलों में भाजपा सरकार के विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं का संदेश अब घर-घर और गांव-गांव तक पहुंचेगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे जनता के बीच जाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से रखें तथा भाजपा की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाएं।

कांग्रेस ने दतिया विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया – भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व पटल पर नई पहचान बना चुका है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश भी विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। डबल इंजन की सरकार विकसित भारत और विकसित मध्यप्रदेश के संकल्प को तेजी से साकार कर रही है। भाजपा सरकार ने जनकल्याण, अधोसंरचना, गरीब कल्याण, किसान हित और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनकी जानकारी प्रचार रथों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक पहुंचेगी। कांग्रेस के पास जनता को बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए वह केवल आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की बात वही कर सकता है जिसने वास्तव में विकास किया हो। कांग्रेस ने अपनी सरकार के दौरान दतिया विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया और पिछले ढाई वर्षों में भी जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी।

कांग्रेस की राजनीति परिवारवाद तक सीमित रही है– भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति उसका संगठन और समर्पित कार्यकर्ता हैं। भाजपा में किसी व्यक्ति की पहचान उसके परिवार या राजनीतिक विरासत से नहीं, बल्कि उसके परिश्रम, समर्पण और संगठन के प्रति निष्ठा से होती है। यही भाजपा की कार्यसंस्कृति है, जिसने एक सामान्य कार्यकर्ता श्री आशुतोष तिवारी को दतिया विधानसभा उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया है। भाजपा में हर कार्यकर्ता के लिए आगे बढ़ने के समान अवसर हैं।

ईशावस्याम महोत्सव–2026

करुणाधाम में 23 जुलाई से होगा त्रिदिवसीय सर्वभौम दिग्विजय महायज्ञ

भोपाल । नेहरू नगर स्थित करुणाधाम आश्रम में ईशावस्याम महोत्सव-2026 के तहत श्री महालक्ष्मी देवालय 11वां स्थापना महोत्सव 23 से 25 जुलाई तक त्रिदिवसीय सर्वभौम दिग्विजय महायज्ञ का आयोजन होगा। इस महायज्ञ में प्रतिदिन 1500 आहुतियाँ अर्पित की जायेंगी। आश्रम के श्री शाश्वत शाण्डिल्य ने बताया कि पीठाधीश्वर गुरुदेव श्री सुदेश जी शाण्डिल्य महाराज के सानिध्य में प्रथम दिवस पंचांग प्रयोग, जल यात्रा, अथर्व पूजन, मंडल स्थापना, अरणी मंथन द्वारा अग्नि स्थापना, आचार्य पूजन होगा। दूसरे दिन नित्य पूजन, ब्राह्मण वरण, दक्षिण अग्नि स्थापना, वाजपेय, राजसूय, सौत्रामणि, चन्द्रष्ठून तथा शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा घृत आहुतियां दी जाएंगी। तुरीय संगीत के साथ द्वितीय दिवस का अनुष्ठान संपन्न होगा। तीसरे दिन 25 जुलाई को नित्य पूजन, वेद मंत्रों से आहूतियाँ, अथर्व की शोभा यात्रा, वैदिक अखाड़ों का नेतृत्व यजमान करेंगे। कन्याओं द्वारा नृत्य प्रस्तुति, आरती भण्डारे के साथ त्रिदिवसीय अनुष्ठान पूर्ण होगा।

कार्यक्रम अनुसार प्रतिदिन सुबह 8ञ्30 से पूजन-हवन होगा। शनिवार 25 जुलाई को पूजन-हवन के उपरांत दोपहर 12ञ्30 बजे पूर्णाहुति होगी। इसी दिन शाम 7ञ्30 बजे माता महालक्ष्मी की दिव्य आरती की जायेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 23 और 24 जुलाई को रात्रि 8 बजे से किया गया है।

गुरमखेड़ी स्टेशन पर 7 दिन नहीं रुकेंगी 8 ट्रेनें

रेलवे के ब्लॉक के कारण अस्थायी बदलाव, 24 से 30 जुलाई तक स्टेशन पर होगा कार्य

भोपाल (नप्र)। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के गुरमखेड़ी रेलवे स्टेशन पर आधुनिकीकरण और रेल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए होने वाले कार्य का असर भोपाल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी पड़ेगा। ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के चलते 24 से 30 जुलाई तक सात दिनों के लिए गुरमखेड़ी स्टेशन पर आठ ट्रेनों का ठहराव अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया है।

रेलवे के अनुसार स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाने, परिचालन क्षमता में सुधार और आधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए यह कार्य किया जा रहा है। इस दौरान कई एक्सप्रेस और मेमू ट्रेनों का गुरमखेड़ी स्टेशन पर निर्धारित ठहराव नहीं होगा। हालांकि इन ट्रेनों का संचालन अपने तय मार्ग पर जारी रहेगा।

पुस्तक 'विधान से जनकल्याण' का विमोचन

भोपाल। मध्यप्रदेश की पहली विधानसभा की प्रथम बैठक की 70वीं वर्षगांठ के अवसर तथा नारी शक्ति वंदन के अवसर पर दो विशेष सत्रों का आयोजन, मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा के युवा विधायकों का सम्मेलन, वेल ऑफ द हाउस के विधानसभा सचिवालयीन अधिकारियों के लिए विशेष गणवेश की व्यवस्था तथा दिवगंत विधानसभा अध्यक्षों एवं मुख्यमंत्रियों की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम की शुरुआत जैसे नवाचार 16वीं विधान सभा के दो वर्षीय कार्यकाल की यादगार उपलब्धियां हैं। सत्र समाप्त तो प्रश्न नहीं होंगे समाप्त, प्रथम निर्वाचित सदस्यों को बोलने के ज्यादा अवसर, मंगलवार को सिर्फ महिला एवं प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों के ही प्रश्न लिये जाने जैसे निर्णय इस कार्यकाल की प्रशंसनीय पहल मानी गई है। इन विशिष्टताओं रेखांकित करती एक पुस्तक विधान से जनकल्याण- 16वीं विधानसभा कार्यकाल के 2 वर्ष का विमोचन हुआ। इस पुस्तक का विमोचन पंचम विधानसभा के सदस्य, पूर्व मंत्री तथा पूर्व विधायक मंडल के अध्यक्ष जसवंत सिंह और नवम विधानसभा के सदस्य तथा पूर्व विधायक परिषद के अध्यक्ष विजेन्द्र सिंह सिसोदिया द्वारा किया गया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में हुए इस आयोजन में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय,, विधायक अरुण भीमावद, विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा सहित अन्य विशिष्टगण उपस्थित थे।

इस पुस्तक में 16वीं विधानसभा के दो वर्ष के कार्यकाल में सदन में अध्यक्ष श्री तोमर द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण वक्तव्यों व व्यवस्थाओं, विधान सभा की समितियों एवं उनके सशक्तिकरण के लिए किये गये प्रयासों, सदस्यों के लिए सुविधाओं के विस्तार हेतु किये गये कार्यों, नवाचारों, विधान सभा में आयोजित प्रमुख संसदीय सम्मेलनों, विशेष सत्रों, ई-विधान, राष्ट्रकुल संसदीय सम्मेलन/पीठासीन अधिकारी सम्मेलनों में अध्यक्ष तोमर की सहभागिता एवं संसदीय, संवैधानिक तथा सम-सामयिक विषयों पर अध्यक्ष तोमर द्वारा समय-समय लिखे गये आलेखों को समाहित किया गया है।

गौरतलब है कि विधायी समितियों को सशक्त व प्रभावी बनाने हेतु लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समिति प्रणाली की समीक्षा हेतु पीठासीन अधिकारियों की समिति का गठन किया है।

करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने गिफ्ट-डीड पर 18 लाख खर्च किए

मर्डर के लिए 1.05 लाख के दो कट्टे खरीदे, रिटायर्ड दंपत्ति हत्याकांड की हकीकत

भोपाल (नप्र)। भोपाल के चर्चित ऐशबाग बुजुर्ग दंपत्ति हत्याकांड में पुलिस रिमांड के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया है कि यह दोहरी हत्या केवल एक अपराध नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए की संपत्ति को हड़पने की सुनियोजित और खौफनाक साजिश थी।

मुख्य आरोपी श्रीकांत और उसके भाई शशिकांत की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें जूडिशल कस्टडी (जेल) में भेज दिया गया है। पुलिस अब डिजिटल, फॉरेंसिक और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर मजबूत चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है।

1. गिफ्ट डीड और रुपयों का दबाव (18 लाख का खर्च)

आरोपी श्रीकांत ने बुजुर्ग दंपत्ति के मकान को अपने नाम कराने के लिए गिफ्ट डीड बनवाने में करीब 18 लाख रुपए खर्च किए थे। उसने शकुंतला को 3 लाख रुपए नकद भी दिए थे। इतना बड़ा आर्थिक निवेश करने के बाद उस पर रुपयों का दबाव बढ़ गया था। उसे उम्मीद थी कि 6 महीने से 1 साल के अंदर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर वह करोड़ों का मकान बेच देगा। जल्द कब्जा पाने के लालच में उसने मर्डर प्लान किया।

2. भाई को आधा मकान बेचने का लालच

हत्या की साजिश में अपने भाई शशिकांत को शामिल करने के लिए श्रीकांत ने उसे बड़ा लालच दिया। उसने वादा किया कि मकान बिकने के बाद जो भी करोड़ों रुपए मिलेंगे, उसमें से आधा हिस्सा शशिकांत का होगा। इसी लालच में शशिकांत भी वारदात में शामिल हो गया।

3. 1.05 लाख में खरीदे गए दो देशी कट्टे

वारदात में इस्तेमाल दोनों देशी कट्टे मालवा क्षेत्र से खरीदे गए थे। श्रीकांत ने एक कट्टा 50 हजार और दूसरा 55 हजार रुपए में खरीदा था। अब पुलिस की जांच का मुख्य फोकस अवैध हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क पर है। सप्लाई चेन से जुड़े तस्करों को चिह्नित कर उन पर अलग से कार्रवाई की जा रही है।

4. भाभी शिवानी को क्लीन चिट, लेकिन 10 लाख के फ्रॉड का एंगल

शकुंतला की भाभी शिवानी बारीक की हत्या की साजिश में कोई भूमिका सामने नहीं आई है, इसलिए पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। हालांकि, जांच में यह बात सामने आई कि श्रीकांत ने शिवानी का 42 लाख रुपए का प्लॉट बेचा था, लेकिन उन्हें सिर्फ 32 लाख रुपए ही दिए। आरोपी ने पूछताछ में इस 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी को कबूला है, जिसकी पुलिस अलग से जांच कर रही है।

संपादकीय

एंडी बर्नहैम के सामने चुनौतियां

ब्रिटेन में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच सत्तासीन लेबर पार्टी के दिग्गज नेता एंडी बर्नहैम ने प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है। ब्रिटेन में पिछले एक दशक में वो देश के सातवें प्रधानमंत्री हैं। एंडी बर्नहैम को बीते हफ्ते शुक्रवार को ही पार्टी का नया मुखिया चुन लिया गया था। बर्नहैम ने उन्हें लेबर पार्टी का नेता चुने जाने को पिछले 40 वर्षों में देश की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव बताया था। नए प्रधानमंत्री के रूप में बर्नहैम ने देश की व्यवस्था को नए सिरे से गढ़ने और सरकार का ध्यान महंगाई, बढ़ती जीवन-यापन लागत के साथ कमजोर होती सार्वजनिक सेवाओं जैसे आम लोगों के मुद्दों पर केंद्रित करने का संकल्प लिया। 56 वर्षीय बर्नहैम ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर रहने के दौरान 'किंग ऑफ द नॉर्थ' के नाम से चर्चित रहे। बर्नहैम को प्रधानमंत्री बनाने की चार सप्ताह की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेबर पार्टी का नेता चुने जाने के बाद बर्नहैम को राजा ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री कीएर स्टारमर की देश अपनी घटती लोकप्रियता के कारण उनकी ही पार्टी के सांसद उनके खिलाफ हो गए थे। नतीजतन उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बर्नहैम को बधाई देते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वह एंडी बर्नहैम के साथ मिलकर भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने तथा साझा विजन 2035 को आगे बढ़ाने के लिए काम करने को लेकर उत्साहित हैं। उधर सत्ता संभालते ही बर्नहैम ने कहा कि उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सत्ता का विकेंद्रीकरण करेगी और निर्णय लेने की ताकत देश के हर क्षेत्र तक पहुंचाएगी। आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को अधिक मजबूत सार्वजनिक नियंत्रण में लाकर उन्हें आम लोगों के लिए फिर से किफायती बनाया जाएगा। बर्नहैम ने अपनी सरकार को 'ब्रिटेन के लिए सर्किट ब्रेकर' बताते हुए कहा कि उनकी सरकार देश में पिछले 40 वर्षों के सबसे बड़े बदलाव लागू करेगी। ब्रिटेन को नए राजनीतिक और आर्थिक मॉडल की जरूरत है। बहरहाल नए प्रधानमंत्री बनहैम के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। ये हैं आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक। ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को सुधारना तथा पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप में चल रहे युद्धों के बीच ब्रिटेन के हितों को संरक्षित करना। बताया जाता है कि बर्नहैम लंदन से ब्रिटेन के अन्य क्षेत्रों में सत्ता का बड़ा हस्तांतरण करना चाहते हैं। उनका मानना है कि इससे असमानता कम होगी और उन पिछड़े समुदायों का गुस्सा शांत होगा जो अब 'रिफॉर्म यूके' पार्टी की तरफ जा रहे हैं। लेबर पार्टी के सांसदों को डर था कि वे 2029 के अगले चुनाव में नाइजेल फराज की पार्टी 'रिफॉर्म यूके' से अपनी सीटें हार सकते हैं। रिफॉर्म यूके पिछले कई महीनों से ओपिनियन पोल में सबसे आगे चल रही है। हालांकि हाल के हफ्तों में अमीर दानदाताओं से फंड लेने के कारण फराज की पार्टी की छवि को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। इससे बर्नहैम को लेबर पार्टी की स्थिति मजबूत करने का मौका मिल सकता है। जहां तक राजनीतिक चुनौती की बात है तो ब्रिटेन में अगले आम चुनाव में तीन साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में बर्नहैम को अपने वादों को जल्द से जल्द लागू करना होगा। आर्थिक विकास से जुड़े स्वतंत्र संगठन 'इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट' के कार्यकारी निदेशक नाइजेल विलकॉक ने कहा कि बर्नहैम ने आर्थिक विकास के एक अलग दृष्टिकोण के लिए वर्षों तक पैरवी की है। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदलने की है। सबसे बड़ी चुनौती को ब्रिटेन को राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने की है। बर्नहैम भी पद पर कब तक टिकते हैं, देखना होगा।

नजरिया

संजय सक्सेना
लेखक लखनऊ निवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं।

जंतर-मंतर की तीन तस्वीरें और राजनीतिक संदेश

दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को जो तस्वीर बनी, वह महज एक विरोध प्रदर्शन की तस्वीर नहीं थी। संसद से जंतर-मंतर तक हाथों में तख्तियां लेकर बढ़ते समाजवादी पार्टी के सांसद, पुलिस कार्रवाई से परेशान युवाओं के बीच बैठी डिंपल यादव, सरकार पर सीधे सवाल उठाती इकरा हसन और आक्रामक तेवरों में नजर आतीं प्रिया सरोज इन तीन चेहरों ने उत्तर प्रदेश की 2027 की राजनीति की एक संभावित तस्वीर जरूर सामने रख दी है। सवाल यह नहीं है कि सोमवार के प्रदर्शन में कौन शामिल हुआ। असली सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अब अपनी राजनीति को तीन अलग-अलग महिला चेहरों के जरिए नई सामाजिक और भौगोलिक जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है? सोमवार को नीट परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और युवा जुटे थे। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रदर्शनकारियों ने सरकार से परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और युवाओं के सवालों पर संवाद की मांग की। इसी प्रदर्शन के समर्थन में समाजवादी पार्टी के सांसद संसद परिसर से जंतर-मंतर की ओर मार्च करते हुए पहुंचे। डिंपल यादव के साथ इकरा हसन और प्रिया सरोज की मौजूदगी ने इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रूप से और ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। डिंपल यादव ने छात्रों के सवालों का समर्थन किया और कहा कि युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरों में वह आंदोलनकारियों के बीच दिखाई दीं।

यही तस्वीरें अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में पढ़ी जा रही हैं। वजह साफ है। 2027 का विधानसभा चुनाव अब दूर की बात नहीं है। चुनाव आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2027 में तय समय पर होने हैं। राज्य में 403 विधानसभा सीटें हैं और इस चुनाव का असर सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करेगा। समाजवादी पार्टी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव एक बड़ा राजनीतिक मोड़ था। पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 37 पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी 33 सीटों पर रह गई और कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीती थीं और समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर रही थी। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव ने राज्य की राजनीतिक जमीन पर विपक्ष के लिए नई संभावनाएं पैदा कर दीं। अब अखिलेश यादव की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोकसभा चुनाव में बने सामाजिक गठजोड़ को 403 विधानसभा सीटों तक कैसे पहुंचाया जाए।यहीं डिंपल यादव की भूमिका सबसे पहले सामने आती है। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव अब सिर्फ यादव परिवार की राजनीतिक विरासत से जुड़ा चेहरा नहीं रह गई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मैनपुरी सीट पर 2,21,639 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। यह जीत बताती है कि उनका व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभाव लगातार मजबूत हुआ है। उनका अंदाज अखिलेश यादव की आक्रामक राजनीति से अलग है। वह तीखे भाषणों की जगह संयमित भाषा, महिला मुद्दों और संवेदनशील राजनीतिक छवि के जरिए अपनी जगह बनाती हैं।

बीजेपी की राजनीति में महिला मतदाताओं का महत्व पिछले एक दशक में लगातार बढ़ा है। उज्ज्वला, आवास, शौचालय, राशन और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों के जरिए बीजेपी ने महिलाओं के बीच एक मजबूत राजनीतिक आधार बनाया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह महिला मतदाताओं तक अपनी सीधी पहुंच बनाए। डिंपल यादव इस चुनौती का जवाब बन सकती हैं। उनके पास पार्टी का पारंपरिक आधार है, लेकिन उनकी छवि उस आधार से आगे जाने की क्षमता भी रखती है। दूसरा चेहरा इकरा हसन का है। कैराना से लोकसभा पहुंचीं इकरा हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग तरह की आवाज बनकर उभरी हैं। उनका राजनीतिक अंदाज सीधे सवाल पूछने वाला है। पश्चिमी यूपी में किसान, युवा, शिक्षा, रोजगार और अल्पसंख्यक राजनीति एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। यहां कोई भी राजनीतिक चेहरा तभी मजबूत होता है, जब वह स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय बहस से जोड़ सके। इकरा हसन के सामने यही अवसर है।उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी युवा पहचान है। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव उस पीढ़ी के बीच लड़ा जाएगा, जिसके लिए सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाएं जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा हैं। नीट विवाद, पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवालों ने युवाओं के बीच बेचैनी पैदा की है। जंतर-मंतर का प्रदर्शन इसी असंतोष को राजनीतिक आवाज देने की कोशिश था। ऐसे मुद्दों पर इकरा हसन जैसे चेहरे सीधे युवाओं से जुड़ सकते हैं।

तीसरा चेहरा प्रिया सरोज का है। मछलीशहर से सांसद प्रिया सरोज 18वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसदों में शामिल हैं। पीआरएस इंडिया के अनुसार उनकी उम्र 27 वर्ष है और लोकसभा में उनकी उपस्थिति 97 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह आंकड़ा उनके संसदीय कामकाज को लेकर उनकी सक्रियता दिखाता है। वह सिर्फ युवा चेहरा नहीं हैं, बल्कि पूर्वांचल के उस सामाजिक और राजनीतिक भूगोल से आती हैं, जहां जातीय प्रतिनिधित्व आज भी चुनावी समीकरणों का सबसे बड़ा आधार है। अखिलेश यादव का पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की राजनीति का केंद्रीय संदेश बना। लेकिन कोई भी राजनीतिक फॉर्मूला केवल नारों से जमीन पर मजबूत नहीं होता। उसके लिए चेहरे चाहिए। डिंपल यादव महिला और पिछड़े वर्गों के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ा सकती हैं। इकरा हसन अल्पसंख्यक और युवा राजनीति की आवाज बन सकती हैं। प्रिया सरोज वंचित और दलित-पिछड़े सामाजिक समूहों के बीच पार्टी की नई पीढ़ी का चेहरा बन सकती हैं। यही इस तिकड़ी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। यह सिर्फ तीन सांसदों का साथ नहीं है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल को जोड़ने वाली संभावित राजनीतिक रेखा है। डिंपल के पास अनुभव और स्वीकार्यता है। इकरा के पास बेबाकी और युवा ऊर्जा है। प्रिया के पास नई पीढ़ी की राजनीतिक पहचान है। अगर सपा इन तीनों चेहरों को अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार सक्रिय करती है, तो यह प्रयोग पार्टी के लिए चुनावी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।

हालांकि बीजेपी के लिए चुनौती को केवल इन तीन महिला सांसदों की लोकप्रियता से जोड़ना जल्दबाजी होगी। राजनीति में वायरल तस्वीरें वोट में तभी बदलती हैं, जब उनके पीछे संगठन खड़ा हो। 2024 में समाजवादी पार्टी की सफलता के बावजूद 2027 का विधानसभा चुनाव पूरी तरह अलग होगा। लोकसभा चुनाव में मुद्दों का प्रभाव व्यापक होता है, जबकि विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर की मशीनरी, स्थानीय उम्मीदवार और जातीय समीकरण निर्णायक होते हैं। सपा को यह साबित करना होगा कि डिंपल, इकरा और प्रिया की लोकप्रियता सिर्फ संसद और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है।बीजेपी के पास भी मजबूत संगठन, सत्ता का अनुभव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। 2022 में बीजेपी ने 403 में से 255 विधानसभा सीटें जीती थीं। इसलिए सपा के सामने सिर्फ सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की चुनौती नहीं है। उसे सत्ता के मजबूत संगठनात्मक ढांचे को चुनौती देनी होगी। यही कारण है कि तीनों महिला सांसदों की भूमिका केवल भाषणों या प्रदर्शनों से तय नहीं होगी। उन्हें गांव, कस्बे, विश्वविद्यालय, महिला समूह और युवा संगठनों के बीच लगातार दिखाई देना होगा। फिर भी जंतर-मंतर की तस्वीर को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि इस तस्वीर में तीन ऐसे राजनीतिक संदेश एक साथ दिखाई दिए, जिन पर 2027 का चुनाव टिक सकता है युवा असंतोष, महिला राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक प्रतिनिधित्व। अगर इन तीनों मुद्दों को सपा लगातार जमीन पर ले जाती है, तो अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला केवल जातीय समीकरण नहीं रहेगा, बल्कि नए चेहरों और नए मुद्दों के साथ एक व्यापक राजनीतिक अभियान बन सकता है।

डिंपल यादव की संवेदनशीलता, इकरा हसन की बेबाकी और प्रिया सरोज की युवा ऊर्जा फिलहाल एक राजनीतिक संभावना है। इसे चुनावी ताकत में बदलना समाजवादी पार्टी की रणनीति पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि सोमवार को जंतर-मंतर पर जो तस्वीर बनी, उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया सवाल जरूर खड़ा कर दिया है क्या 2027 में बीजेपी के सामने अखिलेश यादव का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ पीडीए नहीं, बल्कि उसके साथ खड़ी यह नई महिला राजनीतिक तिकड़ी भी होगी?उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं। गठबंधन बदलेंगे, उम्मीदवार बदलेंगे, मुद्दे बदलेंगे और चुनावी नारों का रंग भी बदलेगा। लेकिन राजनीति में कुछ तस्वीरें समय से पहले संकेत दे देती हैं। जंतर-मंतर की वह तस्वीर भी शायद ऐसी ही तस्वीर है। अगर समाजवादी पार्टी ने इन तीनों चेहरों को सिर्फ संसद की सीमाओं में बंद नहीं रखा और उन्हें उत्तर प्रदेश की जमीन पर लगातार उतारा, तो डिंपल यादव, इकरा हसन और प्रिया सरोज 2027 के चुनाव में बीजेपी के लिए सिर्फ विपक्षी सांसद नहीं, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक मोर्चा बन सकती हैं, जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।

प्रतिभा पलायन

अरूण कुमार डनायक
लेखक समाजसेवी हैं।

क्या भारत अपनी वैज्ञानिक पूँजी सहेज पाएगा?

हाल के महीनों में इसरो के लगभग एक सौ से अधिक वैज्ञानिकों और तकनीकी अधिकारियों के त्यागपत्रों ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या भारत फिर से अपनी वैज्ञानिक पूँजी खोने लगा है? क्या यह केवल सामान्य कर्मचारी परिवर्तन है, या इसके पीछे विज्ञान प्रशासन और नौकरशाही की संरचनात्मक समस्या है? यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के सबसे महत्वाकांक्षी दौर में प्रवेश कर चुका है। गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना, चंद्रयान-4, मंगलयान-2, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, अगली पीढ़ी के संचार एवं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह— इन परियोजनाओं की सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि अनुभवी वैज्ञानिकों पर निर्भर है। वरिष्ठ वैज्ञानिकों का अनुभव और संस्थागत ज्ञान तत्काल प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। डॉ. जितेन्द्र सिंह का यह कथन— 'बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग आते हैं'—सामान्य प्रशासनिक दृष्टि से भले स्वाभाविक लगे, किंतु अंतरिक्ष विज्ञान में वैज्ञानिक विशेषज्ञता का महत्व इससे कहीं अधिक है। इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत संतुलित रही, फिर भी दोनों वक्तव्य त्यागपत्रों के मूल कारणों पर मौन हैं।

स्वतंत्र भारत के सामने वैज्ञानिक प्रतिभाओं का अभाव सबसे बड़ी चुनौती थी। नेहरू ने विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को यह भरोसा दिलाया कि देश उन्हें उनकी क्षमता के अनुरूप अवसर देगा। परिणामस्वरूप अनेक प्रतिभाएँ लौटीं और भारत के वैज्ञानिक भविष्य की नींव रखी। प्रो. यू. आर. राव ने अमेरिका का शोध-करियर छोड़ भारत लौटकर उपग्रह कार्यक्रम को दिशा दी और इसरो को विश्वसनीय संस्थान बनाया। लगभग सात दशक बाद परिदृश्य चिंताजनक रूप से बदलता दिखाई देता है। कभी जिस इसरो ने विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों को स्वदेश लौटने के लिए प्रेरित किया था, आज वही संगठन अपने अनुभवी वैज्ञानिकों को संस्थान में बनाए रखने की चुनौती से जूझ रहा है। हाल के महीनों में इसरो के लगभग एक सौ से अधिक वैज्ञानिकों और तकनीकी अधिकारियों के त्यागपत्रों ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या भारत फिर से अपनी वैज्ञानिक पूँजी खोने लगा है? क्या यह केवल सामान्य कर्मचारी परिवर्तन है, या इसके पीछे विज्ञान प्रशासन और नौकरशाही की संरचनात्मक समस्या है? यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के सबसे महत्वाकांक्षी दौर में प्रवेश कर चुका है। गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना, चंद्रयान-4, मंगलयान-2, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, अगली पीढ़ी के संचार एवं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह– इन परियोजनाओं की सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि अनुभवी वैज्ञानिकों पर निर्भर है। वरिष्ठ वैज्ञानिकों का अनुभव और संस्थागत ज्ञान तत्काल प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। डॉ. जितेन्द्र सिंह का यह कथन– 'बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग आते हैं '–सामान्य प्रशासनिक दृष्टि से भले स्वाभाविक लगे, किंतु अंतरिक्ष विज्ञान में वैज्ञानिक विशेषज्ञता का महत्व इससे कहीं अधिक है। इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत संतुलित रही, फिर भी दोनों वक्तव्य त्यागपत्रों के मूल कारणों पर मौन हैं।

वैज्ञानिकों के बढ़ते त्यागपत्रों के बीच 14 जुलाई 2026 को अंतरिक्ष विभाग ने गगनयान सहित राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं से जुड़े वैज्ञानिकों के त्यागपत्रों पर अंतिम निर्णय का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। यदि स्थिति सामान्य होती, तो ऐसी असाधारण व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। स्पष्ट है कि प्रशासनिक आश्वासनों से अधिक आवश्यकता इसके वास्तविक कारणों की निष्पक्ष समीक्षा की है।

निजी अंतरिक्ष उद्योग का विस्तार वैज्ञानिकों के त्यागपत्रों का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। वर्ष 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने और 2023 की भारतीय अंतरिक्ष नीति लागू होने के बाद देश में चार सौ से अधिक अन्तरिक्ष स्टार्टअप विकसित हुए हैं। बेहतर वेतन, नेतृत्व के अवसर, स्टॉक विकल्प और अपेक्षाकृत तेज़ निर्णय-प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से अनुभवी वैज्ञानिकों को आकर्षित करती है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार का सकारात्मक संकेत भी माना जा सकता है। किंतु प्रतिभा पलायन को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। यदि इसके पीछे संस्थागत असंतोष, वैज्ञानिक स्वायत्तता में कमी, निर्णय-प्रक्रिया में घटती भागीदारी और सीमित कैरियर अवसर जैसे कारण भी हैं, तो यह भारत की विज्ञान नीति के लिए गंभीर चेतावनी है। भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों में लंबे समय से यह चिंता व्यक्त की जाती रही है कि अनेक महत्वपूर्ण तकनीकी निर्णयों में वैज्ञानिक नेतृत्व की अपेक्षा सामान्य प्रशासनिक तंत्र का प्रभाव अधिक होता जा रहा है। विज्ञान और अंतरिक्ष जैसे अत्यधिक विशिष्ट क्षेत्रों में भी कई बार अंतिम निर्णय ऐसे अधिकारियों के हाथों में होता है, जिनकी विशेषज्ञता प्रशासनिक प्रबंधन में होती है, वैज्ञानिक अनुसंधान में नहीं। फलस्वरूप वर्षों के शोध और तकनीकी अनुभव से तैयार वैज्ञानिक अनुशंसाएँ फाइलों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अपना मूल स्वरूप खो बैठती हैं। निस्संदेह किसी भी संस्थान के सुचारु संचालन के लिए प्रशासन अनिवार्य है, किंतु जब वह वैज्ञानिक विवेक का विकल्प बनने लगे, तो शोध, नवाचार और निर्णय-प्रक्रिया प्रभावित होना स्वाभाविक है। प्रश्न यह नहीं कि प्रशासनिक अधिकारी सक्षम हैं या नहीं, बल्कि यह है कि अत्यधिक विशिष्ट वैज्ञानिक निर्णयों में अंतिम प्राथमिकता वैज्ञानिक विशेषज्ञता को मिले या सामान्य प्रशासनिक दृष्टिकोण को। विज्ञान प्रशासन का उद्देश्य वैज्ञानिक निर्णयों को सुगम बनाना होना चाहिए, उनका विकल्प बनना नहीं। नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान की जाक्सा जैसी संस्थाओं में वैज्ञानिकों का उद्योग, विश्वविद्यालय और सरकारी अनुसंधान संस्थानों के बीच आवागमन सामान्य है। इस गतिशीलता को प्रतिभा पलायन नहीं, बल्कि ज्ञान परिसंचरण माना जाता है। चीन ने विदेशों में प्रशिक्षित अपने वैज्ञानिकों को योजनाबद्ध ढंग से स्वदेश लौटाया और उन्हें विश्वस्तरीय अनुसंधान वातावरण उपलब्ध कराया। यही नीति आज उसकी वैज्ञानिक प्रगति की प्रमुख आधारशिलाओं में से एक है। इसके विपरीत भारत अब तक विदेशों में कार्यरत अपनी वैज्ञानिक प्रतिभाओं को बड़े पैमाने पर वापस लाने की कोई प्रभावी और दीर्घकालिक नीति विकसित नहीं कर पाया है। यद्यपि समय-समय पर रामानुजन फेलोशिप, रामालिंगास्वामी री-एंट्री फेलोशिप, वज्र तथा हाल में वैभव जैसे कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं, जिनसे अनेक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक भारतीय संस्थानों से जुड़े भी हैं, किंतु इन्हें अभी तक व्यापक राष्ट्रीय प्रतिभा-वापसी नीति का रूप नहीं मिल सका है।

त्यागपत्रों पर प्रशासनिक रोक अल्पकालिक समाधान हो सकती है, किंतु दीर्घकालीन नहीं। प्रतिभा को आदेश से रोका जा सकता है, लेकिन उत्कृष्टता केवल विश्वास और सम्मान से ही अर्जित की जा सकती है। भारत के सामने बड़ा प्रश्न यह है कि पिछले एक दशक में विदेशों में कार्यरत कितने भारतीय वैज्ञानिक स्थायी रूप से वापस लौटे? क्या हमारे पास ऐसी कोई व्यापक राष्ट्रीय नीति है जो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को पुनः देश के अनुसंधान संस्थानों से जोड़ सके? प्रतिभा संरक्षण के साथ-साथ प्रतिभा वापसी को भी राष्ट्रीय विज्ञान नीति का अभिन्न भाग बनाना होगा। इसरो का संकट केवल एक संस्थान का संकट नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक नीति की परीक्षा है। यदि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखता है, तो उसे केवल रॉकेट, उपग्रह और अंतरिक्ष स्टेशन नहीं बनाने होंगे; उसे ऐसे संस्थान भी बनाने होंगे जहाँ वैज्ञानिक सम्मान, स्वायत्तता और सृजनात्मक स्वतंत्रता के साथ काम करना चाहें। स्वतंत्र भारत ने कभी यू. आर. राव जैसी प्रतिभाओं को स्वदेश लौटने का विश्वास दिलाया था; आज आवश्यकता उस विश्वास को पुनः स्थापित करने की है। राष्ट्र केवल प्रक्षेपण यानों से अंतरिक्ष शक्ति नहीं बनते, वे उन वैज्ञानिकों के विश्वास से बनते हैं जो अपना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अपने ही देश को समर्पित करने का निर्णय लेते हैं। विज्ञान में प्रतिभा पलायन केवल मानव संसाधन का नुकसान नहीं होता; उसके साथ वर्षों का संस्थागत अनुभव, तकनीकी स्मृति और भविष्य की अनेक संभावनाएँ भी चली जाती हैं। यदि भारत 21वीं सदी में वैज्ञानिक महाशक्ति बनना चाहता है, तो उसे वैज्ञानिकों को रोकने की नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जहाँ प्रतिभाएँ लौटना भी चाहें और जीवन भर योगदान देना भी।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

जवाहर चौधरी
लेखक व्यंग्यकार हैं।

हमें बारूद-युद्ध की नहीं हग-युद्ध की जरूरत

चुनाव के चार दिन किसी के लिए कुछ भी हों राजनीति वालों के लिए मानो बेटी का ससुराल होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति सामने पड़े फ़ट्ट से झुक जाओ, चट्ट से चरण छू लो या फिर बनता हो तो लपक के हग कर लो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग ज्यादा प्रसिद्ध हुआ या हग यह देखने वाली बात है। हग दो तरफा क्रिया होती है इसलिए इज्जत भी रह जाती है। पता ही नहीं पड़ता कि कौन किसको कर रहा है। दोनों सीना भिड़ाए एक-दूसरे कि पीठ थपकारते हैं, मानो आशीर्वाद दे रहे हों। दोनों अपना बड़प्पन क्लेम कर लेते हैं। इसलिए जब भी जरूरत महसूस हो तो झपट कर हग करें और ससम्मान खुश रहें। यह चुनाव के समय की स्थिति है। सामान्य वक्तों में बशीर बद्र का कहना सही है.. 'कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से; ये नये मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो।'

माना जाता है कि लोकतंत्र में चुना हुआ व्यक्ति जनता के प्रति जवाबदार होता है लेकिन हकीकत यह है कि वह किसीको जवाब नहीं देता है। अघोषित सूत्र यह है कि जो सबके प्रति जवाबदार हो वह किसी के प्रति जवाबदार नहीं होता। अगर वह ठान ले कि जवाब नहीं देना है तो कोई भले ही अनशन पर बैठ जाए, उसका मुंह नहीं खुलवा सकता है। जनसंख्या जब करोड़ों में हो तो वादे नशा सात्विक होता है। इसमें आदमी संसार में रह कर भी संसार का नहीं होता है। राजनीति वाले इस बात की गहराई को समझते हैं ।

दुनियादारी का ज्ञान रखने वाले हमारे मित्र सरदार पहाड़सिंह एक ही बात कहते हैं कि- 'राजनीति बड़ी कुत्ती-चीज होती है जी'। अवश्य होती होगी, अभी तक किसी शहरी-गैरशहरी कुत्ती-चीज ने आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। आज की राजनीति का ऐसा है कि वह पट्टे और प्राइज टैग वाली होती जा रही है। जिन्हें आपत्ति दर्ज कराना होती है वे अक्सर दुम हिलाने लग जाते हैं । लोग उनके नक्शेकदम अपनी पार्टियाँ व निष्ठाएँ तक बदलने में देर नहीं करते हैं। वैश्विक राजनीति में भी इसी प्रकार की कुत्ती-अदाएं दिखाई देती है। कौन कब गुर्राने लगेगा, कब किस पर झपट पड़ेगा कुछ कहा जा सकता है ? करना चाहिए। पिछले वादों पर नए वादों की धूल डालना आसान होता है। तमाम वादे हों तो लोग भ्रमित रहते हैं। नए वादों के नीचे पुराने वादे दफन हो जाते हैं। धीरे-धीरे जनता वादों और नेताओं से ऊब कर भजन कीर्तन में लग जाती है। धर्म को अफीम भी कहा गया है। अफीम का दुनिया देख रही है कि शांति का पुरस्कार नहीं मिले तो माय-फ्रेंड किस तरह सफ़ेद कबूतर कि गर्दन मरोड़ कर मिसाइल दागने लगता है।

असल बात यह है कि दुनिया में शांति कायम रखना है तो बारूद-युद्ध नहीं हग-युद्ध की जरूरत है। जिसने आगे बढ़ कर हग किया उसे फट्ट से उतना ही हग मिला। सोचिए अमेरिकी और ईरानी लड़ाके दनादन हग करें तो अखबारों की हेडलाइन इत्र से छपने लगेंगी। देसी राजनीतिक संबंधों में भी हग एक शोध का विषय हो सकता है। जो हग के कीड़े हैं वे हग की ताकत जानते हैं। अपना देसी वाला हग थोड़ा अलग होता है । बाजार को हग का मुनाफा मालूम है। सुन है एक लाफ्टर शो वाला हग हग के अरबपति और नंबर वन हो गया है । समय का संकेत है कि 'गले पड़ के' धंधा करो । कंपटीशन बहुत है। संस्थान सोच रहे हैं कि अब रिसेप्शनिस्ट के साथ-साथ हगीस्ट भी रखना पड़ेंगे । रिसर्च वाले कह रहे हैं कि मेल-फीमेल दोनों हगेरियंस की मांग में जबरदस्त उछाल आने वाला है। बाजार और राजनीति के उसूलों में ज्यादा अंतर नहीं है। धंधों में काम अलग-अलग हो सकता है लेकिन नियत एक ही होती है। तो चलिए, निकलिए बाहर, हग-मार्केट की ओर चलते हैं।

पुण्य स्मरण

बृजमोहन श्रीवास्तव

राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी

अजित दादा पवार : लोकतांत्रिक नेतृत्व की अविस्मरणीय विरासत

मेरे लिए अजित दादा केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने संवेदनशीलता, स्पष्टवादिता, प्रशासनिक दक्षता और संगठनात्मक लोकतंत्र को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाया। मैंने उन्हें अनेक अवसरों पर निकट से देखा और पाया कि वे निर्णय लेने से कभी नहीं डरते थे, किंतु हर महत्वपूर्ण निर्णय को जनता और संगठन की सामूहिक सहमति से जोड़कर देखते थे। यही गुण उन्हें समकालीन राजनीति में विशिष्ट बनाता था। भारतीय राजनीति में संकट का समय किसी भी नेतृत्व की वास्तविक परीक्षा होता है। जब राजनीतिक असहमति, कानूनी विवाद और मीडिया की चुनौतियाँ एक साथ सामने हों, तब अधिकांश नेता या तो रक्षात्मक हो जाते हैं अथवा निर्णयों को सीमित दायरे में समेट देते हैं। किंतु अजित दादा ने विपरीत परिस्थितियों में भी संगठनात्मक लोकतंत्र पर अपना विश्वास बनाए रखा। इस संदर्भ में 30 नवम्बर 2023 को कर्जत में आयोजित राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यकारी समिति (एनसीडब्ल्यूसी) और महासभा की बैठक विशेष महत्व रखती है। उस समय पार्टी एक साथ राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर संघर्ष कर रही थी।

22 जुलाई को पहली बार ऐसा अवसर आया है जब अजित दादा पवार हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनका जन्मदिवस हमें उनके व्यक्तित्व, नेतृत्व और राजनीतिक दृष्टि को पुनः स्मरण करने का अवसर देता है। किसी भी सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसके पदों या उपलब्धियों से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि उसने कठिन परिस्थितियों में किस प्रकार नेतृत्व किया और अपने संगठन को कौन-सी दिशा दी। मेरे लिए अजित दादा केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने संवेदनशीलता, स्पष्टवादिता, प्रशासनिक दक्षता और संगठनात्मक लोकतंत्र को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाया। मैंने उन्हें अनेक अवसरों पर निकट से देखा और पाया कि वे निर्णय लेने से कभी नहीं डरते थे, किंतु हर महत्वपूर्ण निर्णय को जनता और संगठन की सामूहिक सहमति से जोड़कर देखते थे। यही गुण उन्हें समकालीन राजनीति में विशिष्ट बनाता था। भारतीय राजनीति में संकट का समय किसी भी नेतृत्व की वास्तविक परीक्षा होता है। जब राजनीतिक असहमति, कानूनी विवाद और मीडिया की चुनौतियाँ एक साथ सामने हों, तब अधिकांश नेता या तो रक्षात्मक हो जाते हैं अथवा निर्णयों को सीमित दायरे में समेट देते हैं। किंतु अजित दादा ने विपरीत परिस्थितियों में भी संगठनात्मक लोकतंत्र पर अपना विश्वास बनाए रखा। इस संदर्भ में 30 नवम्बर 2023 को कर्जत में आयोजित राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यकारी समिति (एनसीडब्ल्यूसी) और महासभा की बैठक विशेष महत्व रखती है। उस समय पार्टी एक साथ राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर संघर्ष कर रही थी। संगठन विभाजित हो चुका था, चुनाव आयोग में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर कानूनी विवाद चल रहा था। फलस्वरूप कार्यकर्ताओं के बीच स्वाभाविक रूप से असमंजस का वातावरण था।

ऐसी परिस्थितियों में सामान्यतः पार्टियों में नेतृत्व निर्णयों को सीमित दायरे में रखता है, किंतु अजित दादा ने इसके विपरीत रास्ता चुना। उन्होंने राष्ट्रीय महासभा के समक्ष प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय को खुलकर रखने, उस पर चर्चा कराने और सामूहिक स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया। उनका यह दृष्टिकोण केवल संगठनात्मक प्रक्रिया के लिये नहीं था, बल्कि संगठन की लोकतांत्रिक राजनीति के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता का प्रमाण था।

आज जब अधिकांश राजनीतिक दलों में निर्णय शीर्ष नेतृत्व तक सीमित हो जाते हैं, तब कर्जत का वह सम्मेलन यह संदेश देता है कि किसी भी दल की वास्तविक शक्ति उसके साधारण कार्यकर्ता में निहित होती है। अजित दादा का स्पष्ट मत था कि संगठन का अंतिम अधिकार महासभा और कार्यकर्ताओं के पास होना चाहिए। नेतृत्व का दायित्व मार्गदर्शन देना है, अधिकार अपने पास केंद्रित करना नहीं।

मुझे आज भी उनके भाषण की वह स्पष्टता याद है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि पार्टी अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। अजित दादा ने न तो परिस्थितियों को छिपाने का प्रयास किया और न ही किसी प्रकार की भावनात्मक राजनीति का सहारा लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि राजनीतिक संघर्ष और कानूनी लड़ाई दोनों समानांतर चलेंगी और इन दोनों का सामना

संगठन की सामूहिक शक्ति से किया जाएगा। उनका यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने न्यायालय, चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को लोकतंत्र का अभिन्न अंग माना। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि संस्थाएँ महत्वहीन हैं; बल्कि उनका विश्वास था कि राजनीतिक और संगठनात्मक वैधता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। चुनाव आयोग में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह की लड़ाई उनके लिए केवल एक कानूनी विवाद नहीं थी, बल्कि संगठन की लोकतांत्रिक स्वीकृति की परीक्षा भी थी।

30 नवम्बर 2023 को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अजीत दादा का पाँच साल के लिये निर्वाचन तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पदाधिकारियों का पाँच वर्षों के लिए निर्वाचन भी इसी व्यापक सोच का हिस्सा था। यह केवल संगठनात्मक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि उस समय चल रहे राजनीतिक और कानूनी संघर्ष के बीच पार्टी को स्पष्ट दिशा देने का प्रयास था। उस दिन कर्जत में दिया गया अजित दादा का भाषण समय की सीमाओं से परे एक राजनीतिक दस्तावेज के रूप में देखा जाना चाहिए। उसमें केवल तत्कालीन परिस्थितियों का उत्तर नहीं था, बल्कि यह संदेश भी था कि किसी भी लोकतांत्रिक संगठन को संकट की घड़ी में किस प्रकार कार्य करना चाहिए। उनका विश्वास था कि पारदर्शिता से संगठन कमजोर नहीं होता, बल्कि और अधिक मजबूत बनता है। खुली चर्चा असहमति को जन्म नहीं देती, बल्कि विश्वास को मजबूत करती है।

आज जब भारतीय राजनीति में दलों के आंतरिक लोकतंत्र पर निरंतर बहस होती रहती है, तब अजित दादा की कार्यशैली हमें यह स्मरण कराती है कि संगठन की स्थायी शक्ति केवल चुनावी सफलता से नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के विश्वास से निर्मित होती है। यही विश्वास किसी भी राजनीतिक दल को लंबे समय तक जीवंत बनाए रखता है। अजित दादा पवार के नेतृत्व का सबसे बड़ा संदेश यही था कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि संस्थाओं, संविधान और संगठनात्मक मूल्यों के प्रति उत्तरदायित्व निभाने का भी माध्यम है। नेतृत्व का अर्थ केवल निर्णय लेना नहीं, बल्कि लोगों को निर्णय प्रक्रिया का सहभागी बनाना भी है। आज उनके जन्मदिवस पर उन्हें स्मरण करना केवल श्रद्धांजलि देना नहीं है। यह उस लोकतांत्रिक दृष्टि को याद करने का अवसर भी है, जिसमें कार्यकर्ता सर्वोच्च है, संवाद सबसे बड़ी शक्ति है और कानून तथा संविधान संघर्ष के सबसे विश्वसनीय आधार हैं।

यदि हम वास्तव में अजित दादा पवार को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो हमें उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी सीख को आत्मसात करना होगा–संगठन विश्वास से चलता है, भय से नहीं; लोकतंत्र संवाद से मजबूत होता है, गोपनीयता से नहीं; और नेतृत्व वही है जो सबसे कठिन समय में भी चट्टान की तरह अडिग रहकर अपने साथियों का विश्वास बनाए रखें। इसी संकल्प के साथ हम सब उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

सरोकार

ब्रजेश कानूनगो

लेखक स्तंभकार हैं।

सस्ते सौदे की असली कीमत

हाल के महीनों में वियतनाम द्वारा नकली लक्जरी सामानों के विरुद्ध चलाया गया व्यापक अभियान केवल कानून-व्यवस्था की कार्रवाई नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक व्यापार की नई वास्तविकता का संकेत भी है। अमेरिका लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि वियतनाम नकली ब्रांडेड वस्तुओं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर और चीनी उत्पादों के पुनः निर्यात का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। अमेरिकी दबाव और ऊँचे आयात शुल्क की आशंकाओं के बीच वियतनाम सरकार ने बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की। हो ची मिन्ह सिटी सहित अनेक स्थानों पर हजारों नकली उत्पाद जब्त किए गए और ऑनलाइन बिक्री नेटवर्क पर भी शिकंजा कसा गया। वियतनाम अकेला नहीं है। हाल के वर्षों में अमेरिका, हांगकांग, थाईलैंड और कई अन्य देशों ने भी नकली लक्जरी वस्तुओं के विरुद्ध अभियान तेज किए हैं। यह इसलिए भी आवश्यक हो गया है क्योंकि नकली सामानों का कारोबार अब केवल कुछ फुटपाथी दुकानों तक सीमित नहीं रहा। यह संगठित अपराध, कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा बहु-अरब डॉलर का वैश्विक कारोबार बन चुका है।

आज किसी भी बड़े शहर के बाजार, पर्यटन स्थल या ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर 'फर्स्ट कॉपी', 'मिरर कॉपी' और 'एएए कॉपी' जैसे शब्द आम हो चुके हैं। महंगे ब्रांडों के जूते, बैग, घड़ियाँ, कपड़े, इत्र और चश्मे उनकी वास्तविक कीमत के छोटे से हिस्से में उपलब्ध मिल जाते हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि अधिकांश खरीदार जानते हैं कि वे नकली वस्तु खरीद रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई अपराधबोध नहीं होता। उनके लिए यह कम कीमत में प्रतिष्ठा का अनुभव खरीदने जैसा सौदा है। यही इस समस्या की सबसे बड़ी चुनौती है। नकली सामानों का बाजार केवल आर्थिक कारणों से नहीं, बल्कि सामाजिक मनोविज्ञान के कारण भी फल-फूल रहा है। लक्जरी ब्रांड आज उपयोगिता से अधिक सामाजिक पहचान का माध्यम बन चुके हैं। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और तीव्र किया है। तस्वीरों और वीडियो की दुनिया में वस्तु की गुणवत्ता से अधिक उसका लोगो दिखाई देता है। ऐसे में यदि कम कीमत पर वही बाहरी स्वरूप मिल जाए तो अनेक उपभोक्ता उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करते।

नकली उत्पाद बनाने वालों के लिए भी यह अत्यंत लाभकारी कारोबार है। उन्हें न अनुसंधान पर खर्च करना पड़ता है, न डिज़ाइन, गुणवत्ता परीक्षण, विज्ञापन या ब्रांड निर्माण पर। वे केवल प्रसिद्ध ब्रांड की पहचान का अनुचित लाभ उठाकर कम लागत में भारी मुनाफा अर्जित करते हैं। यही कारण है कि यूरोप, अमेरिका, चीन, तुर्किये, दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत सहित अनेक देशों में यह समानांतर बाजार लगातार विस्तार कर रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। दिल्ली के पालिका बाजार से लेकर मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत और जयपुर जैसे शहरों तक नकली ब्रांडों का कारोबार वर्षों से चलता आ रहा है। अब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने इसे और व्यापक बना दिया है। सोशल मीडिया और छोटे ई-कॉमर्स माध्यमों के जरिए नकली उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुँच रहे हैं। कई बार उपभोक्ता स्वयं भी यह पहचान नहीं पाता कि उसने असली वस्तु खरीदी है या उसकी नकल। इसका दूसरा पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मूल ब्रांड बनाने वाली कंपनियाँ वर्षों तक अनुसंधान, डिज़ाइन, गुणवत्ता नियंत्रण और विपणन पर भारी निवेश करती हैं। नकली उत्पाद बिना किसी बौद्धिक या वित्तीय निवेश के उसी प्रतिष्ठा का लाभ उठा लेते हैं। इससे केवल उनकी बिक्री प्रभावित नहीं होती, बल्कि ब्रांड की विश्वसनीयता और विशिष्टता भी कमजोर पड़ती है। यदि कोई उपभोक्ता खराब गुणवत्ता वाले नकली उत्पाद को असली समझ ले, तो उसके मन में ब्रांड की छवि भी धूमिल हो सकती है। दीर्घकाल में यह नवाचार और अनुसंधान पर निवेश के उत्साह को भी प्रभावित करता है।

लेकिन इसका प्रभाव केवल कंपनियों तक सीमित नहीं रहता। नकली वस्तुओं के कारण सरकारों को कर राजस्व का नुकसान होता है, वैध उद्योगों में रोजगार प्रभावित होता है और संगठित अपराध को आर्थिक आधार मिलता है। इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि दवाइयों, सौंदर्य प्रसाधनों, विद्युत उपकरणों और वाहन के पुर्जों जैसे क्षेत्रों में नकली उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।

हालाँकि इस बहस का एक दूसरा पक्ष भी है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। कई विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ लक्जरी ब्रांड अपनी वास्तविक उत्पादन लागत की तुलना में अत्यधिक ऊँचे मूल्य वसूलते हैं। उपभोक्ता का बड़ा भुगतान उत्पाद की उपयोगिता के बजाय उसकी ब्रांड छवि और विशिष्टता के लिए होता है। परिणामस्वरूप अनेक लोग यह महसूस करते हैं कि वे केवल नाम के लिए अत्यधिक कीमत चुका रहे हैं। यह धारणा भी नकली उत्पादों की मांग को बढ़ाती है। इसलिए समस्या केवल अवैध कारोबार की नहीं, बल्कि अत्यधिक महंगी उपभोक्ता संस्कृति की भी है।

स्पष्ट है कि इस चुनौती का समाधान केवल छापेमारी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकता। बौद्धिक संपदा कानूनों का प्रभावी पालन, सीमा शुल्क एजेंसियों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर नकली उत्पादों की त्वरित पहचान और हटाने की व्यवस्था तथा आधुनिक डिजिटल प्रमाणीकरण तकनीकों का व्यापक उपयोग आवश्यक होगा। क्यूआर कोड, ब्लॉकचेन आधारित सत्यापन और डिजिटल प्रमाणपत्र जैसी तकनीकें इस दिशा में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। इसके साथ ही ब्रांड कंपनियों को भी आत्ममंथन करना होगा। यदि वे बेहतर गुणवत्ता के साथ अपेक्षाकृत सुलभ मूल्य वाली उत्पाद श्रृंखलाएँ विकसित करें, तो नकली बाजार का आकर्षण स्वाभाविक रूप से घट सकता है। भारत जैसे देशों में स्थानीय गुणवत्ता आधारित ब्रांडों को प्रोत्साहन देकर उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और किफायती विकल्प उपलब्ध कराना भी दीर्घकालिक समाधान का हिस्सा होना चाहिए।

दरअसल नकली लक्जरी वस्तुओं का कारोबार केवल सस्ती खरीदारी का प्रश्न नहीं है। यह उपभोक्ता मनोविज्ञान, सामाजिक प्रतिष्ठा, वैश्विक व्यापार, कानून, नवाचार और नैतिकता के जटिल अंतर्संबंधों का परिणाम है। जब तक कम कीमत में प्रतिष्ठा पाने की मानसिकता बनी रहेगी, तब तक नकली बाजार भी किसी न किसी रूप में जीवित रहेगा। इसलिए आवश्यक है कि सरकारें प्रभावी कानून लागू करें, कंपनियाँ मूल्य और उपलब्धता के बीच संतुलन स्थापित करें तथा उपभोक्ता भी मौलिकता और गुणवत्ता के महत्व को समझें। स्वस्थ और निष्पक्ष बाजार व्यवस्था की रक्षा का यही सबसे टिकाऊ मार्ग है।

राष्ट्रीय ध्वज दिवस पर विशेष

श्वेता गोयल

लेखक शिक्षक हैं।

संविधान और संप्रभु भारत का अमर प्रतीक तिरंगा

राष्ट्रीय ध्वज दिवस भारत की सम्प्रभु राष्ट्र बनने की यात्रा का स्मरण कराता है। तिरंगा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता के लिए इसके कठिन संघर्ष और एकजुट एवं समृद्ध राष्ट्र के लिए अपने लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। हमारा राष्ट्र ध्वज न केवल राष्ट्र की एकता, अखंडता, गरिमा, गौरव, शक्ति, आदर्श और आकांक्षाओं का प्रतीक है बल्कि समूचे विश्व को त्याग की भावना एवं शाति का संदेश भी देता है। यह हमारी स्वतंत्रता का भी प्रतीक है क्योंकि आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों को एकजुट करने में इसकी बहुत अहम भूमिका रही। तिरंगे ने ही भारतवासियों को एकता और भाईचारे का संदेश देकर उन्हें एक सूत्र में पिरोकर अंग्रेजों से लोहा लेने को प्रेरित किया था।

विश्व में प्रत्येक राष्ट्र का अपना-अपना राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज ही उसकी मर्यादा और अस्मिता से जुड़ा होता है लेकिन इस मायने में हमारा राष्ट्र ध्वज 'तिरंगा' अन्य राष्ट्र ध्वजों के मुकाबले अनेक विशेषताएं धारण किए हुए है। चूंकि अंग्रेजों से भारत की मिली आजादी के चंद दिन पहले ही 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान भारतीय तिरंगे को देश के आधिकारिक ध्वज के रूप में अपनाया था, इसीलिए भारत में प्रतिवर्ष 22 जुलाई को 'राष्ट्रीय ध्वज दिवस' मनाया जाता है। आधिकारिक रूप में तिरंगे को अपनाने के बाद से यह देश की एकता, साहस, और आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया। राष्ट्रीय ध्वज दिवस भारत की सम्प्रभु राष्ट्र बनने की यात्रा का स्मरण कराता है। तिरंगा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता के लिए इसके कठिन संघर्ष और एकजुट एवं समृद्ध राष्ट्र के लिए अपने लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। हमारा राष्ट्र ध्वज न केवल राष्ट्र की एकता, अखंडता, गरिमा, गौरव, शक्ति, आदर्श और आकांक्षाओं का प्रतीक है बल्कि समूचे विश्व को त्याग की भावना एवं शाति का संदेश भी देता है। यह हमारी स्वतंत्रता का भी प्रतीक है क्योंकि आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों को एकजुट करने में इसकी बहुत अहम भूमिका रही। तिरंगे ने ही भारतवासियों को एकता और भाईचारे का संदेश देकर उन्हें एक सूत्र में पिरोकर अंग्रेजों से लोहा लेने को प्रेरित किया था। तब क्रांतिकारियों के लिए राष्ट्र ध्वज का सम्मान अपने प्राणों से भी बढ़कर होता था, इसीलिए अंग्रेजों की लाठियां व गोलियां खाते हुए भी उन्होंने इसे कभी झुकने नहीं दिया।

तीन रंगों की पट्टियों वाले राष्ट्रीय ध्वज की सबसे ऊपर की केसरिया रंग की पट्टी त्याग, बल और पौरूष की प्रतीक है जबकि बीच वाली सफेद पट्टी शांति और सत्य की प्रतीक है और सबसे नीचे की हरे रंग की पट्टी हरियाली, समृद्धि एवं सम्पन्नता की प्रतीक है। झंडे के बीचों-बीच सफेद पट्टी में स्थित गहरे नीले रंग का अशोक चक्र आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। 24 तीलियों वाला अशोक चक्र देश की प्रगति, राष्ट्र के कानून और धर्म के पहिये का प्रतीक है। डा. सर्वपल्ली राधकृष्णन के शब्दों में कहें तो जो लोग इस ध्वज के नीचे कार्य करेंगे, उन्हें सत्य और सदाचार के सिद्धांतों का पालन करना होगा। राष्ट्र ध्वज के नीचे कार्य करने वालों से उनका तात्पर्य सरकारों और नौकरशाहों से था। राष्ट्र कोकिला सरोजिनी नायडू ने भी राष्ट्र ध्वज की महत्ता का उल्लेख करते हुए संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज का प्रस्ताव पेश करते समय 22 जुलाई 1947 को कहा था कि नए भारत के सभी नागरिकों को इस राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करना होगा और इसके नीचे कोई छोटा-बड़ा नहीं होगा।

राष्ट्र ध्वज का सफर 7 अगस्त 1906 को आरंभ हुआ था। हरे, पीले और लाल रंग की तीन पट्टियों से बना यह राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता के पारसी बागान में फहराया गया था। उस ध्वज पर ऊपर की हरी पट्टी पर एक ही पंक्ति में सफेद रंग के आठ कमल अंकित थे जबकि बीच वाली पीली पट्टी पर देवनागरी में गहरे नीले रंग से वंदेमातरम् लिखा था और नीचे की लाल पट्टी पर बायीं ओर एक सफेद सूर्य और दायीं ओर एक-एक सफेद चन्द्रमा और तारा अंकित थे। 'भारत का झंडा' नामक यह ध्वज हालांकि भारत के सभी धर्मों, सम्प्रदायों और साम्प्रदायिक सद्भावना को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया था लेकिन यह ध्वज सर्वमान्य नहीं हो पाया। 1917 में डॉ. एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा 'होमरूल आन्दोलन' चलाया गया था। उस समय एक नया राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया गया, जिसमें लाल और हरे रंग की एक के बाद एक कुल 9 समानान्तर और तिरछी पट्टियां थी। उस ध्वज के बीचों-बीच 7 तारे थे और एक कोने में चांद व तारा अंकित थे जबकि उसके ऊपरी बायें कोने में 'यूनियन जैक' का चित्र (झंडे का चौथाई भाग) बनाया गया था। झंडे में यूनियन जैक के इस चित्र को सम्मिलित किए जाने के कारण ही यह अधिकांश लोगों द्वारा नापसंद कर दिया गया क्योंकि इस चित्र को राष्ट्रीय ध्वज में स्थान देने का अर्थ यही माना गया कि भारतीय समाज की ब्रिटिश सम्प्रभुत्ता के प्रति स्वीकृति है। तब एक ऐसे ध्वज की आवश्यकता महसूस की गई, जो प्रत्येक धर्म, सम्प्रदाय और विचारधाराओं के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के साथ देशवासियों के लिए जीवन-मरण का प्रतीक भी बन सके। 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस के अधिवेशन में आंध्र प्रदेश के पिंगली वैंकैया नामक क्रांतिकारी युवक ने महात्मा गांधी को एक ऐसा ध्वज भेंट किया, जिसमें लाल व हरे रंग की केवल दो पट्टियां थी लेकिन पंजाब के एक बुजुर्ग नेता रायजादा पंडित हंसराज ने गांधी जी को सुझाव दिया कि इस ध्वज में चरखे को भी अंकित किया जाए और तब गांधी जी ने यह सुझाव स्वीकारते हुए हिन्दुओं के लिए केसरिया रंग, मुस्लिमों के लिए हरा रंग तथा अन्य सम्प्रदायों के लिए ध्वज में सफेद रंग को भी शामिल किया। 31 दिसम्बर 1929 को रावी नदी के तट पर इसी तिरंगे को फहराते हुए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। हालांकि बहुत से लोगों को राष्ट्रीय ध्वज को जातियों व धर्म-सम्प्रदाय से जोड़ना उचित नहीं लगा, अतः 1931 में राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप के निर्धारण के लिए कराची कांग्रेस ने 7 व्यक्तियों की एक समिति बनाई और समिति ने एक ही रंग (केसरिया) के ध्वज में नीचे बायीं ओर लाल रंग के चरखे का चिन्ह अंकित करने का सुझाव दिया, जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात् पं. जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई और उस बैठक में तिरंगे ध्वज को ही बीच की सफेद पट्टी में चरखे सहित मान्यता प्रदान की गई और उस निर्णय को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह रही कि तीनों पट्टियों के रंगों को धर्म-सम्प्रदायों से न जोड़कर उनके गुणों के आधार पर ही स्वीकार किया गया। इस ध्वज का आकार लम्बाई और चौड़ाई में 3:2 रखा गया।

1924 में आजादी के लिए संघर्षरत श्यामलाल गुप्त 'पार्षद' ने झंडा गीत ''विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा'' की रचना की और महात्मा गांधी ने उस गीत के दूसरे और तीसरे भाग को हटाकर उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। वह गीत पहली बार कानपुर में 1925 में कांग्रेस सम्मेलन में सामूहिक रूप से गाया गया। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोष ने भी इसे एक लाख लोगों के साथ गाया और देखते ही देखते यह गीत क्रांतिकारियों का सबसे लोकप्रिय गीत बन गया। चाहे कांग्रेस का कोई सम्मेलन हो, कोई प्रभात फेरी हो अथवा क्रांतिकारियों का कोई आन्दोलन, ऐसे हर अवसर पर यही झंडा गीत बड़े ही जोशीले अंदाज में गाया जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के चंद दिनों पहले जब भारत के सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक स्वरूप स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज की चर्चा चली तो 1931 में सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए ध्वज को ही पुनः राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया लेकिन 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की एक बैठक में पं. नेहरू ने चरखे के स्थान पर इसमें देश की प्रगति, राष्ट्र के कानून और धर्म के पहिये के प्रतीक 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को रखने का सुझाव दिया। संविधान सभा के सभी सदस्य इस सुझाव से सहमत हो गए और उसी दिन से राष्ट्रीय ध्वज को नए रूप में स्वीकार लिया गया। इस प्रकार हमारे राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने के लिए करीब 41 वर्षों का बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा।

पहल

ऋतुपर्ण दवे
लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

एग्रो-होम्योपैथी कृषि क्षेत्र की नई क्रान्ति

होम्योपैथी एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति जरूर है, लेकिन बहुत ही तेजी से लोकप्रिय भी हो रही है। यह रोगी के समग्र स्वास्थ्य जिसमें मानसिक और शारीरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करके प्राकृतिक रूप से शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की ताकत होती है। होमियोपैथी को एक सुरक्षित चिकित्सा पद्धिति माना जाता है क्योंकि इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन सोचिए, यही होमियोपैथी यदि कृषि के क्षेत्र में भी उपयोगी साबित हो तो इसे किसी चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता। इन दिनों दुनिया भार में एग्रो-होमियोपैथी पर लेकर न केवल बड़े-बड़े शोध चल रहे हैं बल्कि तेजी से उपयोग भी बढ़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है।

कृषि क्षेत्र में इसका सफल प्रयोग कई दशकों से हो रहा है। इसकी शुरुआत हालाकि शौकिया तौर पर हुई, लेकिन जब इसके फायदे नजर आने लगे तो तेजी से शोध और परीक्षण भी होने लगे और लोगों की इसको लेकर उत्सुकता भी बढ़ी। अब नतीजे भी दिखने लगे हैं। होम्योपैथी दवाओं के टिंचर की कुछ बूंदे थोड़े से पानी में मनुष्यों को देकर यह विश्वास उत्पन्न किया जाता है कि यह बीमारी की जड़ तक पहुंच उसका समाधान करता है। बस यही फॉर्मूला कृषि क्षेत्र में भी अपनाया जा रहा है।

वास्तव में होम्योपैथिक दवाएं बैक्टीरिया या कीटों को सीधे नहीं मार, पौधों की अपनी जैविक प्रणालियों को प्रभावित करती हैं जिससे वो अपना प्राकृतिक रक्षा तंत्र, जरूरत के हिसाब से विकसित और सक्रिय कर पाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में होम्योपैथी का उपयोग उसी सिध्दांत पर आधारित है जिसमें किसी बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए धीरे-धीरे डायल्यूट दवाओं से किसी बीमारी को काबू किया जाता है जिससे वह जड़ से ही समाप्त हो जाती है। यह पौधों की आनुवंशिक गतिविधियों और चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रेरित कर सकता है, जिससे रक्षा प्रणालियां सक्रिय होती हैं।

देश में एग्रो-होम्योपैथी को लेकर पुडुचेरी प्रयोग खासा सफल और चर्चाओं में है। श्री अरबिंदो सोसाइटी (एसएएस) की अगुवाई में एक नई पहचान बन रही है। एग्रो-होम्योपैथी से दोहरा लाभ भी सामने आया। जहां पानी की खपत घटी और इस कारण भूजल स्तर भी बढ़ा। 2018 में शुरू हुई आहार परियोजना में कृषि क्षेत्र में होम्योपैथी के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए शुरु हुए इस प्रोजेक्ट की सफलता का अंदाज इसी से लगता है कि कुछ ही समय में इसे नाबार्ड और उसके बाद टाटा ट्रस्ट का समर्थन मिला। वैज्ञानिक प्रयोगों के बाद जब यह फॉर्मूला खेतों में पहुंचा तो वहां भी बेहद असरकारक रहा। पहले भिंडी उसके बाद धान की उपज में काफी सकारात्मक परिणाम आए। उत्साहित वैज्ञानिकों ने तीनों सीजन रबी, खरीफ और जायद में भी इसकी क्षमता को आजमाया और सकारात्मक नतीजे हासिल किए।इससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ी जिससे रसायनों पर निर्भरता घटी।

सर्वविदित है कि खेतों में उर्वरकों का छिड़काव करने से मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को नुकसान होता है लेकिन कृषि-होम्योपैथी के मिश्रण ने पत्तियों को नई जान तो दी साथ ही पौधों की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाई। शोधकर्ताओं ने कृषि-होम्योपैथी की लागत को बेहद सस्ती पाया। पहले जहां कृषक 20 से 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर रसायनों पर व्यय करता था, वही होम्योपैथिक दवाओं पर केवल 700 रुपए प्रति हेक्टेयर ही खर्च कर और भी बेहतर परिणाम हासिल करने लगा। यह कमाल ही था जो होम्योपैथिक दवाओं की चंद मिलीमीटर दवाओं ने सैकड़ों लीटर पानी में घुले रसायनों पर भारी पड़ कर असर दिखाया। इससे खेती में हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल रुकने से फसल की चमक और पुष्टता भी बेहतर हुई जिससे किसानों को उपज की अच्छी कीमत मिलने लगी।

होम्योपैथी दवाएं वनस्पतियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को जबरदस्त बढ़ाती हैं। इससे वनस्पतियां, फसल होने वाली बीमारी को अपने आप ठीक कर लेते हैं। एग्रो-होम्योपैथी में अलग-अलग और बेहद सस्ती चंद मिलीमीटर दवाएं बीजों के अंकुरण से लेकर रोगों से बचाव और फूलने-फलने को बेहतर बनाने में कारगर सिद्ध हो रही है। ये दवाएं कीट प्रबंधन की दिशा में भी काफी सफल हैं। यहां तक कि फसल में वायरस या बैक्टीरिया के दुष्प्रभावों पर भी असरकारक हैं। वह दिन दूर नहीं जब निरंतर शोध और प्रयोगों के बाद एग्रो-होम्योपैथी की भी ढेरों और अलग-अलग शाखाएं बनना तय है। यह भविष्य का वृहद कृषि पारिस्थितिकी तंत्र होगा। इसमें भी उपचारों की अलग-अलग विधियां होंगी। लेकिन इतना तो तय है कि रसायनों और उर्वरकों के बोझ से आहत मिट्टी को यदि कोई नया जीवन और जहरीले तत्वों से मुक्ति दिलाएगा तो वह होगा भविष्य का एग्रो-होम्योपैथी सेक्टर जहां मिट्टी, पानी अपने मूल स्वरूप में आकर फिर से हमारी प्रकृति में नया जोश भरने का काम करेंगे। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर होम्योपैथी की नई शाखा यानी एग्रो-होम्योपैथी जल्द ही अपनी शानदार धमक दिखाने को तैयार है।

नोटों के संग्रह की अनोखी दीवानगी

बैतूल के रिटायर्ड शिक्षक राजेश के पास हैं, 90 देशों के नोटों का संग्रह

परवेज खान, बैतूल। बैतूल के टिकारी निवासी रिटायर्ड शिक्षक राजेश सूर्यवंशी दुर्लभ नोटो का संग्रह करते हैं। 1970 से जारी नोटों के संग्रह की दीवानगी से उनके पास देशी- विदेशी नोटो का बहुत बडा संग्रह है। इस संग्रह में नए-पुराने नोट एवं सिक्के, मिस प्रिंट एवं दुर्लभ नंम्बर वाले नोट व सिक्के शामिल है। श्री सूर्यवंशी के इस संग्रह में द्वितीय सेंचुरी के भारतीय सिक्के एवं 1938 के पुराने भारतीय दुर्लभ नोट भी जमा है। इनके संग्रह में लगभग 90 देशों के विदेशी नोट एवं सिक्कों का संग्रह है। इसमें प्रमुख इंडोनेशिया का भगवान श्री गणेशजी का 20000 रुपये का नोट, यूगोस्लाविया का 5 करोड़ का नोट जमा है। जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है।

6 देशों की प्लास्टिक करेन्सी उनके पास- श्री सूर्यवंशी के संग्रह में प्लास्टिक करेन्सी में मलेशिया, ग्वाटारमाला, हांगकांग, मेक्सिको, नेपाल रोमानिया, ताशकन्द आदि 6 देशों के नोट है। इन नोटों को आप कभी भी देख सकते है।

अब भारत में प्लास्टिक के नोट निकालने की तैयारी- अब भारत में भी प्लास्टिक के नोट चलाए जाने की तैयारी तेज हो गई है। भारतीय रिजर्व बैक सूत्रों के मुताबिक 10 और 20 के प्लास्टिक के नोट के अगले साल तक आने की उम्मीद है। अभी इसकी टेंडर प्रक्रिया बाकी है। श्री सूर्यवंशी का कहना है कि उन्होंने आर.बी.आई. से जुड़ अधिकारियों से चर्चा की थी। उन्होंने भारत में प्लास्टिक के नोट जारी होने की उम्मीद जताई है। यह सम्भवतः अगले साल मार्च में आ सकते हैं। अगले माह इनके टेंडर हो जाएंगे। इससे प्लास्टिक के नोट जारी करने वाले देशों में भारत भी शामिल हो जाएगा।

दुनिया के 60 देशों में चल रहे प्लास्टिक के नोट- दुनिया के 195 देशों में मात्र 60 देशों में ही प्लास्टिक के नोट प्रचलन में है। यहां उल्लेखनीय है कि आस्ट्रेलिया एवं कनाडा ने पूरी तरह से प्लास्टिक करेन्सी को अपना लिया है। भारत अगर प्लास्टिक के नोट जारी करने में सफल होता है, तो वह ऐसा करने वाला 61वां देश बन जाएगा।

तीन बार हो चुका भारत प्लास्टिक के नोट निकालने में विफल- भारत मे पहले भी नोटों की किल्लत को देखते हुए प्लास्टिक के नोट जारी करने के तीन बार प्रयास हो चुके हैं, लेकिन नोटों को बनाने से जुड़ी कंपनियों के नहीं मिलने से प्रक्रिया विफल हो चुकी है। अब फिर से कंपनी को आमंत्रित किया गया है। इससे इस बार प्लास्टिक के नोट निकलने की उम्मीद जगी है।

कलेक्टर ने जनसुनवाई में सुनीं नागरिकों की समस्याएं

जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का करें त्वरित निराकरण : कलेक्टर सोनवणे

बैतूल। कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे से आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं ध्यान पूर्वक सुनीं। जनसुनवाई के दौरान राजस्व, भूमि विवाद, पेंशन, आवास, बिजली, पानी सहित अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई। इस दौरान उन्होंने कई प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर मौके पर ही निराकरण कराया, वहीं शेष मामलों में समय-सीमा तय करते हुए अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में रामनगर निवासी अशोक नागले ने अतिक्रमण हटाने को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने बैतूल नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया कि संबंधित अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों

को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई में दोबारा न आना पड़े। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट सहित अन्य अधिकारियों ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में महावीर वार्ड टिकारी निवासी श्रीमती सजिता धोटे द्वारा कब्जा दिलाने के आवेदन पर कलेक्टर ने बैतूल तहसीलदार को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश। बैतूल निवासी प्रमिला द्वारा सीमांकन के आवेदन पर कलेक्टर ने राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। आठनेर निवासी सुभाष चंद्र द्वारा अतिक्रमण कर्ताओं पर कार्यवाही किए जाने के आवेदन पर तहसीलदार आठनेर और नगर परिषद सीएमओ आठनेर को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत दनोरा जीन के ग्रामीणों ने आवेदन के माध्यम से शुगर मिल द्वारा अपशिष्ट पदार्थ एवं हानिकारक जल ग्राम के नाले में छोड़े जाने से पंचायती नल जल के कुएं दूषित होने की शिकायत पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को जांच कर प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए।

समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए अर्जित ज्ञान का करें उपयोग : कौशलेश तिवारी

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के विद्यार्थियों को दी सम्मानपूर्ण विदाई

बैतूल। आठनेर में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत समाज कार्य के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का सम्मानपूर्वक विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में विद्यार्थियों से अर्जित ज्ञान को समाज सेवा से जोड़ते हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में सभी फायनल ईयर के विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी गईं। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड आठनेर की विकासखंड समन्वयक मधु चौहान ने जन अभियान परिषद द्वारा पाठ्यक्रम को चलाने के उद्देश्य एवं पूरे सत्र की गतिविधियों का प्रतिवेदन उपस्थित लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए परिषद के नर्मदापुरम संभाग समन्वयक कौशलेश तिवारी ने कहा कि सीएमसीएलडीपी पाठ्यक्रम समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा,संवेदना और विकास की रोशनी पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने अध्ययन से अर्जित ज्ञान एवं कौशल का उपयोग समाज के वंचित,जरूरतमंद और कमजोर वर्गों के उत्थान, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सामाजिक जागरूकता के लिए करें।

जनहित की भावना के साथ कार्य करें : थाना प्रभारी

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आठनेर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार ने कहा कि एक सच्चे समाजसेवी की पहचान उसके समर्पण, नैतिकता, जनसेवा और सकारात्मक नेतृत्व से होती है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने कार्यक्षेत्र में नैतिक मूल्यों,सामाजिक उत्तरदायित्वो एवं जनहित की भावना के साथ कार्य करें, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।समाज कार्य की यह शिक्षा तभी सार्थक होगी जब उसका प्रत्यक्ष लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचेगा। यही पाठ्यक्रम की मूल भावना भी है। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने भी अपने अध्ययनकाल के अनुभव साझा किए तथा संकल्प लिया कि वे समाज के सर्वांगीण विकास, जनजागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण तथा ग्रामीण विकास जैसे सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में निरंतर सक्रिय रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र-छात्राओं को सम्मानपूर्वक विदाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य,सफल जीवन एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान की मंगल कामनाएं व्यक्त की गईं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आठनेर नगर मंडल अध्यक्ष गोवर्धन राने, जनपद सदस्य राजू सलामें सहित ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के पदाधिकारी एवं मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह का समापन सभी के द्वारा एक साथ समरसता भोज ग्रहण कर किया गया।

डागा-पांसे सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज

कांग्रेस संगठन सृजन प्रशिक्षण में हुआ विवाद पहुंचा थाने

बैतूल। जिले में कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों गुटों में एक दूसरे को कमजोर करने के प्रयास तेज होते जा रहे हैं, जो भविष्य में होने वाले नगरीय निकाय, पंचायत, मंडी एवं सहकारिता सहित अन्य चुनावो के हिसाब से कांग्रेस के लिए हितकर नहीं है। राजनैतिक समीक्षकों का भी यही मानना है कि जिस तरह से कांग्रेस में मतभेद के साथ-साथ मनभेद भी सामने आया है, वह पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। इससे भाजपा अपना राजनैतिक लाभ मिलने की उम्मीद कर रही है।

यह है मामला – लगभग 65 वर्ष पूर्व बैतूल में कांग्रेस को कार्यालय बनाने के लिए भूमि प्राप्त हुई थी। लगभग 40 वर्ष तक कांग्रेस, देश और प्रदेश में सत्ता में रही। इसके बावजूद कांग्रेस कार्यालय भवन बैतूल में नहीं बना पाई। वहीं 2003 में बैतूल में जमीन मिलते ही पांच वर्षों में भाजपा ने अपना विशाल कार्यालय खड़ा कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस भवन को लेकर जिला कांग्रेस के प्रवक्ता

एवं जिले में निलय डागा के समर्थक माने जाने वाले विजय पारधी ने कांग्रेस के संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर में आल इंडिया कांग्रेस की ओर से आए मध्यप्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी को बैतूल में इस बारे में बताया कि 15 महीने की सरकार में कांग्रेस कार्यालय की जमीन पर से अतिक्रमण हटने और भूमिपूजन होने के बाद भी भवन नहीं बना। लेकिन निलय डागा ने अध्यक्ष बनते ही कार्यालय का काम चालू कर दिया। इसी बात को लेकर कांग्रेस का दूसरा गुट विजय

पारधी से नाराज हो गया और जैसे ही हरीश चौधरी रवाना हुए, तो विजय पारधी के साथ धक्का-मुक्की का वीडियो भी वायरल हो गया। जिसको लेकर विजय पारधी ने देर शाम थाने में शिकायत दर्ज की। मिली जानकारी के अनुसार विजय पारधी की शिकायत की जानकारी मिलते ही आमला से दो बार कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़कर हारने वाले मनोज मालवे ने भी एक शिकायत कर दी। पुलिस ने दोनों पक्षों पर काउंटर केस दर्ज कर लिया है।

इनके खिलाफ हुआ है मामला दर्ज

कोतवाली टीआई देवकरण डेहरिया ने बताया कि विजय पारधी की शिकायत पर अपराध क्रमांक 602/ 26 के तहत पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, सलमान खान, मनोज मालवे और नवनीत मालवीय के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है। वंही मनोज मालवे की शिकायत पर अपराध क्रमांक 605/ 26 के तहत जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक निलय डागा, विजय पारधी, मोनू बडोनिया और हर्षवर्धन धोटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मारपीट, गाली-गलौज की धाराओं के अलावा एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

रेत और मुरूम के अवैध परिवहन में संलिप्त 2 वाहनों को किया जप्त

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 18 और 19 जुलाई को खनिज विभाग द्वारा खनिज अमले के साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण किया गया। खनिज अमले द्वारा गौण खनिजों के अवैध परिवहन में संलिप्त वाहनों पर कार्यवाही करते हुए उन वाहनों को जप्त कर समीपस्थ पुलिस थानों की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है। खनि निरीक्षक बैतूल द्वारा खनिज अमले के साथ घोड़ाडोंगरी क्षेत्रांतर्गत खनिज मुरूम के अवैध परिवहन में संलिप्त 01 वाहन डम्पर क्रमांक एमपी 48 एच 0735 को जप्त कर पुलिस चौकी घोड़ाडोंगरी की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है एवं बैतूल क्षेत्रांतर्गत ग्राम खेड़ीसांवलीगढ़ के पास से खनिज रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त 01 वाहन जॉन डियर ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 48 एए 1136 को जप्त कर पुलिस चौकी खेड़ीसांवलीगढ़ की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है। उपरोक्त अवैध परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर प्रकरणों को न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है।

जिला जनगणना हस्तपुस्तिका तैयार करने दिया जा रहा प्रशिक्षण

बैतूल। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशन तथा अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी वंदना जाट के मार्गदर्शन में जनगणना-2027 के अंतर्गत जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के निर्माण के लिए आवश्यक आंकड़ों के संकलन एवं डीसीएचबी पोर्टल के प्रभावी संचालन के उद्देश्य से जिले में 17 जुलाई से 28 जुलाई तक पीएमश्री शासकीय एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल में विभिन्न बैचों में प्रशिक्षण संचालित हो रहा है। प्रशिक्षण में जिले के सभी ग्रामीण एवं नगरीय चार्ज अधिकारियों तथा उनके द्वारा नामित क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को जिला जनगणना हस्तपुस्तिका तैयार करने की प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा है।

हरियाली बढ़ाने को लेकर नगर पंचायत परिषद के जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों ने किया सीड बॉल वृक्षारोपण

सोहागपुर। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशन के अनुसार नर्मदापुरम जिले में हरियाली बढ़ाने को लेकर नवांकुर अभियान के अंतर्गत नगर पंचायत परिषद ने सीड बॉल वृक्षारोपण महाअभियान आयोजित किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत परिषद के तत्वावधान में बीज बैंक के माध्यम से तैयार लगभग 4000 सीड बॉल को नगर के शोभापुर रोड स्थित अटल अमृत उद्यान से लेकर नहर के पास, विभिन्न खाली एवं उपयुक्त स्थानों पर डाला गया। वर्तमान में वर्षा ऋतु के दौरान सीड बॉल में मौजूद बीजों के अंकुरित होने से विभिन्न स्थानों पर नए पौधों के विकसित होने की संभावना है। इस हरियाली बढ़ाने के उत्कृष्ट आयोजन नगर पंचायत परिषद ने नागरिकों की सहभागिता के लिए गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया था।इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष लता यशवंत पटेल, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि यशवंत पटेल, उपाध्यक्ष आकाश रघुवंशी, पार्षद रविशंकर उइके, पार्षद आशीष

विश्वकर्मा, संध्या नागवंशी,नीरज मलैया, नगर पंचायत परिषद के समस्त कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक एवं मातृशक्ति उपस्थित थीं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी धर्मेन्द्र शर्मा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार विगत 02 माह से सीड बाल का निर्माण किया जा रहा था। जिसमें अनेकों प्रकार के बीज को एकत्रित करवा कर सीड बाल का निर्माण कराया गया था। जिससे अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जा सके। इस सीडी डाल में आम, जामुन, नीम, कटहल सहित विभिन्न फलदार एवं छायादार वृक्षों के बीज एकत्रित कर सीड बॉल तैयार की गई हैं। इस पहल का उद्देश्य बीजों को सुरक्षित रूप से मिट्टी तक पहुंचाकर प्राकृतिक रूप से पौधों के अंकुरण को बढ़ावा देकर नगर में हरित क्षेत्र को विस्तार करना है। सीड बॉल वृक्षारोपण अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अभिनव एवं प्रभावी पहल है, जिसमें कम संसाधनों के माध्यम से अधिक से अधिक स्थानों पर हरियाली विकसित की जा रही है। नगर पंचायत परिषद ने पर्यावरण संरक्षण के लिए नागरिकों से सहयोग एवं जनभागीदारी की अपील की है। जिसमें 'एक बीज - एक पौधा - एक हरित भविष्य' के संकल्प के साथ पर्यावरण संरक्षण एवं हरित क्रांति के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे है। इस अवसर पर संजय परसाई, दयाशंकर कुड़मी, हक्कूलाल परते, भूपेंद्र केवट, हरगोविंद व्यास, प्रबुद्ध दुबे, अनिल रघुवंशी, नरेंद्र धुर्वे,लक्ष्मीनारायण मालवीय, कपिल सोनी, राधेश्याम रघुवंशी, रणधीर रघुवंशी, राजेश रघुवंशी, लाल बहादुर आम्रवंशी,नीरज मलैया, पवन कुमार, घनश्याम पठारिया, प्रवेश ठाकुर, प्रहलाद किरार आदि उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

दो प्रकरण में नगद इनाम की घोषणा

विदिशा (निप्र)। पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी के द्वारा थाना नटेरन जिला विदिशा में दर्ज अपराध क्रमांक 172/2026 के फरार आरोपी जित्तू उर्फ जितेन्द्र कुशवाह निवासी गंजबासौदा तथा देहात गंजबासौदा जिला विदिशा में दर्ज अपराध क्रमांक 209/2026 के फरार अज्ञात आरोपी की सूचना देने वालो को क्रमशः तीन-तीन हजार रूपए नगद राशि देने की उद्घोषणा की है। सूचनाकर्ता चाहे तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।

वॉटरफॉल एवं जोखिमपूर्ण स्थानों पर जा रहे लोगों को लौटाया जा रहा वापस

कलेक्टर ने वर्षाकाल में जोखिमपूर्ण स्थलों पर न जाने की नागरिकों से की अपील

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरु के. के निर्देशानुसार वर्षाकाल में नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी वॉटरफॉल, डैम, जल पर्यटन स्थलों एवं अन्य जोखिमपूर्ण स्थानों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावी हैं। इन स्थानों पर वर्षा के दौरान दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए राजस्व, वन, पुलिस तथा अन्य विभागों के मैदानी अमले की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि पर्यटकों को प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने से रोका जा सके तथा उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके। कलेक्टर के निर्देशानुसार अमरगढ़, दिगंबर और कालियादेव वॉटरफॉल सहित इन सभी दुर्घटना संभावित स्थलों पर नागरिकों को जाने से रोकने के लिए इनके पहुंच मार्गों पर टीमें तैनात की गई हैं। टीम द्वारा इन स्थानों पर जा रहे लोगों को प्रतिबंधात्मक आदेश की जानकारी देकर वापस लौटाया जा रहा है। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने पर्यटकों से अपील की है कि वे अपनी तथा अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश न करें। नागरिकों का जीवन एवं सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्षाकाल में जिले के इन पर्यटन स्थलों पर सीहोर के साथ-साथ भोपाल से भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। कलेक्टर ने सभी नागरिकों से प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करने तथा सुरक्षित व्यवहार अपनाने की अपील की है।

मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना से 49 जरूरतमंद मरीजों को मिली राहत

विदिशा (निप्र)। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर एवं गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 49 मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन ने विभिन्न अस्पतालों को ई-पेमेंट के माध्यम से सहायता राशि जारी की है। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह राशि सीधे संबंधित अस्पतालों के बैंक खातों में भेजी गई है, जिससे मरीजों का उपचार बिना किसी आर्थिक बाधा के जारी रह सके। जारी सूची के अनुसार जिले की तहसील क्रमशः नटेरन, लटेरी, कुरवाई, गंजबासौदा, सिरोंज, विदिशा, शमशाबाद, ग्यारसपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों के मरीजों को योजना का लाभ मिला है। सहायता राशि 15 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक स्वीकृत की गई है। योजना के तहत जिन प्रमुख अस्पतालों को उपचार राशि जारी की गई उनमें जीवानंद मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, राजधानी हॉस्पिटल, जिंदल हॉस्पिटल, केयरवेल मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, विधाता मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, अरेरा हॉस्पिटल एंड कैथ लैब, एम्स भोपाल, जीवन ज्योति मल्टीकेयर ट्रॉमा सेंटर, हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, गट-जी एंड लीवर हॉस्पिटल, सर्वोत्तम हॉस्पिटल, भोपाल फ्रैक्चर हॉस्पिटल, सागर मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, मैक्स मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लीलावती मेमोरियल हॉस्पिटल, सुश्रुत हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, अवध मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, न्यू एरा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, हर हेल्थ हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल, डॉ. जी.एम. ताओरी सीआईएमएस हॉस्पिटल नागपुर, लक्ष्मी मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, काउंटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एबीएम हॉस्पिटल, ग्रीन सिटी हॉस्पिटल, बेरसिया जनरल हॉस्पिटल, एपेक्स हॉस्पिटल, लेकसिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल साइंस तथा बंसल हॉस्पिटल भोपाल शामिल हैं।

ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर 99 हजार की साइबर ठगी

केरल और मुंबई से दो आरोपी गिरफ्तार, कस्टमर केयर पर किया था कॉल

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम में ऑनलाइन शॉपिंग और फर्जी कस्टमर केयर के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह के दो आरोपियों को नर्मदापुरम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देहात थाना पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर केरल और महाराष्ट्र (मुंबई) में दबिश देकर दोनों आरोपियों को पकड़ा। दोनों आरोपी ग्वालियर जिले के रहने वाले हैं। इनमें से एक मुंबई के विजय नगर औद्योगिक क्षेत्र में चौकीदारी कर रहा था। पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर नर्मदापुरम ले आई है।

कस्टमर केयर नंबर खोजते ही ठगी का शिकार हुई महिला

मामला 18 मार्च 2026 का है। रसूलिया निवासी रूबी फौजदार ने ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर किए थे और फोनपे के जरिए 9 हजार रुपए का भुगतान किया था। भुगतान के बाद बुकिंग की पुष्टि नहीं हुई। जानकारी लेने के लिए उन्होंने इंटरनेट पर कस्टमर केयर नंबर खोजकर कॉल किया। फोन उठाने वाले व्यक्ति ने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताया। उसने पैसे वापस करने का झांसा देकर महिला के बैंक खाते से 99 हजार रुपए निकाल लिए। इसके बाद महिला ने देहात थाने में शिकायत दर्ज कराई।

तकनीकी जांच से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

मामले की जांच के दौरान पुलिस और साइबर सेल ने बैंक खातों के लेनदेन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की। जांच में आरोपियों की लोकेशन केरल और महाराष्ट्र में मिली। पुलिस की टीम सबसे पहले केरल के बटकारा पहुंची। वहां से विकास बाथम निवासी ग्राम देवरीकला, थाना बेलगढ़, जिला ग्वालियर को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपने साथी दीपक रावत निवासी देवरीकला, जिला ग्वालियर का नाम बताया। दीपक रावत उस समय मुंबई के विजय नगर औद्योगिक क्षेत्र में चौकीदारी कर रहा था। पुलिस ने मुंबई पहुंचकर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को नर्मदापुरम लाया गया है। उन्हें रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

बालिका गृह से लापता 5 नाबालिग केस में एसआईटी गठित

■ बीजेपी नेता की है संस्था, जांच करने पहुंचे पुलिस अफसर, बच्चियों से भी की बात

नर्मदापुरम(निप्र)। नर्मदापुरम जिले के इटारसी स्थित मुस्कान बालिका गृह से 5 नाबालिग लड़कियों के लापता होने के मामले में नर्मदापुरम एसपी साईं कृष्णा एस. थोटा ने एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) गठित की है। टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। शनिवार शाम एएसपी अभिषेक राजन के नेतृत्व में इटारसी एसडीओपी वीरेंद्र मिश्रा, इटारसी थाना प्रभारी सौरभ पांडे, महिला थाना प्रभारी राखी मौर्य, पथरौटा थाना प्रभारी मोनिका गौर, महिला एसआई श्रद्धा राजपूत और अन्य अधिकारी मुस्कान बालिका गृह पहुंचे। अधिकारियों ने संस्था की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और वहां रह रही बच्चियों से अलग-अलग बातचीत कर जानकारी जुटाई।

दो साल में 5 लड़कियां लापता

पुलिस के अनुसार जुलाई 2024 में एक, दिसंबर 2025 में तीन और 14 जून 2026 को एक नाबालिग लड़की लापता हुई थी। इस तरह कुल पांच लड़कियां लापता हैं। फिलहाल उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वे कहां हैं और किस स्थिति में हैं। इस जांच में साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है। पुलिस लड़कियों के परिजनों के भी बयान दर्ज करेगी। 17 जुलाई की रात इटारसी थाने में पांचों नाबालिगों की गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई है।

कलेक्टर को भी लिखा गया पत्र

एसपी नर्मदापुरम ने मामले को लेकर कलेक्टर को भी पत्र लिखा है। इसमें लड़कियों की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराने में हुई देरी का उल्लेख किया गया है। साथ ही संस्था में रहवास, खानपान और अन्य सुविधाओं की भी जांच कराने की बात कही गई है।

पुलिस को सूचना देने के दस्तावेज नहीं मिले

जांच के दौरान पुलिस को ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला, जिससे यह साबित हो कि संस्था ने नाबालिग लड़कियों के लापता होने की लिखित सूचना थाने में दी थी। एएसपी अभिषेक राजन ने बताया कि एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। संस्था की ओर से पुलिस को लिखित सूचना देने संबंधी कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया। विस्तृत जांच के बाद पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होगी।

भाजपा नेता चलाते हैं संस्था

जिस मुस्कान बालिका गृह से लड़कियां लापता हुई हैं, उसका संचालन मनीष ठाकुर करते हैं, जो भाजपा से जुड़े हैं। उनकी पत्नी नगर पालिका में सभापति हैं। मनीष ठाकुर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों में सपोर्ट पर्सन के रूप में भी नियुक्त हैं।

बैठक में होगी एक पेड़ माँ के नाम अभियान की समीक्षा

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत किए जा रहे वृक्षारोपण कार्यों की समीक्षा सोमवार, 20 जुलाई 2026 को आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में की जाएगी। जिला पंचायत के सीईओ श्री ओपी सनोडिया ने सभी विभाग प्रमुखों, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) तथा नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (सीएमओ) को निर्देशित किया गया है कि वे वृक्षारोपण वर्ष 2026-27 के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगाए गए पौधों की अद्यतन जानकारी तथा पिछले दो वर्षों में किए गए वृक्षारोपण की उत्तरजीविता (सर्वाइवल रेट) का विवरण निर्धारित गूगल शीट में समय पर दर्ज करें। बैठक में प्रत्येक विभाग की प्रगति का बिंदुवार परीक्षण किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लक्ष्य के अनुरूप पौधारोपण, उनकी देखभाल तथा जीवित पौधों की स्थिति से संबंधित जानकारी पूर्ण एवं प्रमाणिक रूप से प्रस्तुत करें।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित

बैतूल, (निप्र)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 18 जुलाई को जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उप संचालक कृषि श्री राम गोपाल रजक ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य फसल बीमा योजना अंतर्गत कृषकों को जागरूक करना एवं कृषकों को प्राकृतिक कारणों से होने वाले जोखिमों की जानकारी के बारे में बताना एवं व्यक्तिगत क्षति की भरपाई के लिए किस-किस तरीके से सूचनाओं को कैसे दर्ज करते हैं एवं सर्वे कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी उपलब्ध कराना है।

उन्होंने बताया कि बैतूल जिले में खरीफ मौसम 2026 कृषकों को फसल बीमा करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवा कर जोखिमों एवं फसल बीमा के हित लाभ के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वर्तमान खरीफ मौसम 2026 में अधिसूचित फसलों के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि सोयाबीन के लिए 850 रुपए , मक्का 722 रुपए, धान सिंचित के लिए 838 रुपए, धान असिंचित 660 रुपए तथा अरहर के लिए 740 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई हैं। फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करने के इच्छुक किसान अपनी निकटतम बैंक शाखा सहकारी समिति अधिकृत चैनल एवं जन सेवा केंद्र सीएससी एवं कृषक स्वयं भी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.inपर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर योजना से जुड़ सकते है। अऋणी कृषकों को फसल बीमा करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज बैंक पासबुक, फसल बुवाई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, भू अधिकार दस्तावेज एवं बटाईदार किसान या किराए पर ली गई भूमि के लिए भूमि मालिक द्वारा शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य है। इस कार्यशाला में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री हंसराज धुर्वे , श्री दीपक कपूर, श्री भोला खंडेलवाल, कृषि स्थाई समिति सभापति श्री माधोराव नानकर, जनपद सदस्य मुलताई श्री दिलीप पाटेकर, उप संचालक कृषि श्री राम गोपाल रजक, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक श्री आर.डी. बारपेटे, नाबार्ड बैंक जिला प्रबंधक श्री राहुल कुशवाहा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक महाप्रबंधक सुश्री नीता निगम एवं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जिला प्रबंधक श्री राकेश कुमार बेरवा एवं कृषक उपस्थित थे।

दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत जिले में पशुपालकों को वैज्ञानिक पशुपालन के लिए किया जागरूक

बैतूल (निप्र)। दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तृतीय चरण के अंतर्गत जिले के विभिन्न विकासखंडों में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने पशुपालकों से संवाद कर उन्हें वैज्ञानिक पशुपालन, पशु स्वास्थ्य, नस्ल सुधार तथा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उपायों की जानकारी दी गई। अभियान के दौरान शासन की विभिन्न पशुपालन एवं दुग्ध विकास योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई तथा आधुनिक तकनीकों को अपनाकर आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया।

अभियान के तहत विकासखंड शाहपुर के ग्राम भौंरा में घोड़ाडोंगरी विधायक श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके एवं भूतपूर्व जनपद सदस्य श्री अशोक सिरोटिया ने पशुपालकों को नस्ल सुधार, पशु पोषण एवं पशु स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर जागरूक किया। इस दौरान पशुपालकों को गौरस ऐप की जानकारी दी गई तथा अभियान से संबंधित रील भी साझा की गई। क्षीरधारा ग्राम के संबंधित पशुपालक को माननीय विधायक द्वारा चरी-चारा बीज का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में विकासखंड पशुचिकित्सा अधिकारी डॉ. राहुल सिंह एवं सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारी श्री मुकुल चौधरी उपस्थित रहे।

विकासखंड मुलताई के ग्राम मुलताई में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जिला पंचायत बैतूल अध्यक्ष श्री राजा पवार ने पशुपालक श्री प्रदीप पवार के यहां निरीक्षण एवं संवाद किया। इस अवसर पर उन्नत नस्ल के लिए कृत्रिम गर्भाधान एवं सेक्स-सॉर्टेड सीमेन के उपयोग, संतुलित आहार, सायलेज, मिनरल मिक्सचर, कृमिनाशक दवाओं के नियमित उपयोग तथा समय-समय पर टीकाकरण सहित आधुनिक वैज्ञानिक पशुपालन तकनीकों की जानकारी दी गई। साथ ही वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक पशुपालन अपनाकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, उत्पादन लागत कम करने तथा अधिकतम आर्थिक लाभ अर्जित करने के उपायों से अवगत कराया गया। पशुपालक द्वारा बताई गई आवश्यकताओं एवं समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। इस अवसर पर संयुक्त संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग भोपाल डॉ. सुनील परनाम तथा उप संचालक बैतूल डॉ. सुरजीत सिंह उपस्थित रहे।

इसी क्रम में पूर्व संसदीय सचिव एवं पूर्व विधायक , विधानसभा घोड़ाडोंगरी श्री रामजीलाल उइके ने दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तृतीय चरण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉ. कीर्ति ठाकरे एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी श्री मनीराम अहाके उपस्थित रहे। श्री उइके ने पशुपालकों से विभाग द्वारा प्रदाय की जा रही सेवाओं की जानकारी प्राप्त की तथा उन्हें गौरस ऐप का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। विकासखंड के ग्राम बोरदेही में कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने पशुपालक श्री अरविंद से संवाद किया। इस दौरान दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, पशुओं के संतुलित पोषण तथा वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर डॉ.सोनवणे ने विशेष रूप से पशुओं को नियमित रूप से मिनरल मिक्सचर खिलाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसके नियमित उपयोग से पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर रहता है, दुग्ध उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता में सुधार होता है तथा खनिज तत्वों की कमी से होने वाली समस्याओं की रोकथाम होती है।

अवैध शराब परिवहन पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 300 पाव देसी मसाला शराब व बाइक जब्त, आरोपी जेल भेजा

विदिशा (निप्र)। जिले में अवैध मदिरा के धारण, परिवहन, निर्माण एवं विक्रय पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग लगातार अभियान चला रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशानुसार तथा जिला आबकारी अधिकारी श्री विकास त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आबकारी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का परिवहन कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री राजीव थापक एवं श्रीमती साधना पटेल राजपूत के नेतृत्व में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी दल ने भेंरोखेड़ी तिराहा स्थित हैप्पी वाइव रेस्टोरेंट के पास ठठर रोड पर घेराबंदी की। इस दौरान टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल क्रमांक MP40ZG3978 को रोककर उसकी तलाशी ली गई।

तीर्थ दर्शन योजना: 260 श्रद्धालु हरिद्वार-ऋषिकेश रवाना

केंद्रीय मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने दिखाई हरी झंडी

बैतूल (निप्र)। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत बैतूल जिले के लगभग 260 श्रद्धालुओं को रविवार को हरिद्वार-ऋषिकेश की चार दिवसीय तीर्थ यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन द्वारा रवाना किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने बुजुर्ग यात्रियों का पुष्पहार पहनाकर आत्मीय स्वागत किया, उनका आशीर्वाद लिया तथा हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया।

इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री हंसराज धुर्वे, अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती इंदिरा महतो सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

केंद्रीय मंत्री श्री उइके ने कहा

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री उइके ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बुजुर्गों के सम्मान और उनकी आस्था को समर्पित एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि जीवनभर परिवार और समाज की सेवा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने का अवसर देना सरकार की संवेदनशील सोच का परिचायक है। उन्होंने यात्रियों से यात्रा के दौरान आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने, देश की सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने तथा प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी यात्रियों के सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत यह हरिद्वार-ऋषिकेश यात्रा 19 जुलाई से 22 जुलाई 2026 तक आयोजित की जा रही है। यात्रा के लिए बैतूल जिले से कुल 260 यात्रियों का चयन किया गया है। यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक चिकित्सक, पांच आरक्षक तथा पांच अनुरक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इस विशेष तीर्थ यात्रा में बैतूल के साथ नर्मदापुरम एवं सागर जिले के श्रद्धालु भी सहभागी हैं।

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अधिकारी कर रहे पानी के प्लांटों का निरीक्षण

सीहोर (निप्र)। नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा पानी के प्लांटों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर पालिका के कार्यपालन यंत्री श्री विजय कोली एवं उपयंत्री श्री वैभव लोवानिया द्वारा काहिरी प्लांट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जल की गुणवत्ता जांचने के लिए आवश्यक ऑनसाइट टेस्ट किए गए और नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जो कहा वो किया
जो सोचा वो हुआ

क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या राम क्या रहीम,
क्या रविन्दर क्या रॉबर्ट सबके लिये समान कानून

मात्र **2 माह** में 27 अप्रैल 2026 को उच्च स्तरीय समिति
गठन के बाद, 21 जुलाई 2026 को विधानसभा में ऐतिहासिक मंजूरी

विधानसभा में पारित
समान नागरिक संहिता

21 जुलाई 2026
विधानसभा में पारित

27 अप्रैल 2026
उच्च स्तरीय समिति का गठन
7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति द्वारा देश के विभिन्न कानूनों और अन्य राज्यों के UCC मॉडलों का गहन तुलनात्मक अध्ययन

अभूतपूर्व जन-भागीदारी
सुझाव हेतु वेब पोर्टल लॉन्च

3.50 करोड़
संदेश नागरिकों को भेजे गए

10 लाख सुझाव मिले
मध्यप्रदेश के विधायी इतिहास में पहली बार

जिला और राज्य स्तर पर
50+ वृहद बैठकें

व्यावहारिक सुझाव संकलित
1,134+

ऐतिहासिक जनसमर्थन
93%
ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया

92%
पुरुष और महिलाएं समान कानून के पक्ष में

लैंगिक समानता और अधिकार
91%
ने भेदभावपूर्ण तलाक कानून हटाने का समर्थन किया

92%
ने बेटियों और माताओं को संपत्ति में समान अधिकार का समर्थन किया

सर्वसमुदाय का समर्थन
हिन्दू: 95% पुरुष
96% महिलाएं

मुस्लिम: 40% पुरुष
80% महिलाएं

ईसाई: 90% पुरुष
95% महिलाएं

सिख: 93% पुरुष
96% महिलाएं

प्रदेश की आधी आबादी, सभी बहनों को, दिया उनका हक़

D-11064/26